

My Notes.....

राष्ट्रीय

राष्ट्रीय पोषण मिशन की स्थापना को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9046.17 करोड़ रुपये के तीन वर्ष के बजट के साथ 2017-18 से शुरू होने वाले **राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम)** की स्थापना को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। एनएनएम एक शीर्षस्थ निकाय के रूप में मंत्रालयों के पोषण संबंधी हस्तक्षेपों की निगरानी, पर्यवेक्षण, लक्ष्य निर्धारित करने तथा मार्गदर्शन करेगा। इस प्रस्ताव में निम्नलिखित सम्मिलित है:

1. कुपोषण का समाधान करने हेतु **विभिन्न स्कीमों के योगदान का प्रतिचित्रण**।
2. अत्यधिक मजबूत अभिसरण तंत्र प्रारंभ करना।
3. आईसीटी आधारित वास्तविक समय निगरानी प्रणाली।
4. लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना।
5. आईटी आधारित उपकरणों के प्रयोग के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना।
6. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा रजिस्ट्रों के प्रयोग को समाप्त करना।
7. आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों की ऊंचाई के मापन प्रारंभ करना।
8. सामाजिक लेखा परीक्षा।
9. लोगों को जन आंदोलन के जरिए पोषण पर विभिन्न गतिविधियों आदि के माध्यम से शामिल करना, पोषण संसाधन केंद्रों की स्थापना करना इत्यादि शामिल है।

मुख्य प्रभाव:

1. यह कार्यक्रम लक्ष्यों के माध्यम से ठिगनेपन, अल्प पोषाहार, रक्त की कमी तथा जन्म के समय बच्चे के वजन कम होने के स्तर में कमी के उपाय करेगा।
2. इससे बेहतर निगरानी समय पर कार्यवाही के लिए सावधानी जारी करने में तालमेल बिटाने तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मंत्रालय और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को कार्य करने, मार्गदर्शन एवं निगरानी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

वित्तीय परिव्यय

1. वर्ष 2017-18 से प्रारंभ तीन वर्षों के लिए 9046.17 करोड़ रुपये हैं।

कार्यान्वयन रणनीति एवं लक्ष्य

1. राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य ठिगनेपन, अल्पपोषण, रक्ताल्पता (छोटे बच्चों, महिलाओं एवं किशोरियों में) को कम करना तथा प्रति वर्ष अल्पवजनी बच्चों में क्रमशः 2 प्रतिशत, 2 प्रतिशत, 3 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत की कमी लाना है।
2. हालांकि ठिगनेपन को कम करने का लक्ष्य 2 प्रतिशत है, मिशन वर्ष 2022 (2022 तक मिशन 25) तक 38.4 (एनएफएचएस-4) से कम कर के 25 प्रतिशत तक लाने का प्रयास करेगा।

पृष्ठभूमि

1. छह वर्ष से कम आयु के बच्चों और महिलाओं के बीच कुपोषण के मामले से निपटने के लिए सरकार ने कई स्कीमों लागू की हैं।
2. इन योजनाओं के बावजूद देश में कुपोषण तथा संबंधित समस्याओं का स्तर ऊंचा है।
3. योजनाओं की कोई कमी नहीं है किंतु आम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजनाओं को एक-दूसरे के साथ तालमेल स्थापित करने में कमी देखने में आई है। एनएनएम सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित करके वांछित तालमेल को कायम करेगा।

2. इसका सरकारी बजटीय समर्थन (50 प्रतिशत) तथा आईबीआरडी अथवा अन्य एमडीबी द्वारा 50 प्रतिशत वित्त पोषण होगा। केंद्र तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच 60:40 पूर्वोत्तर क्षेत्रों तथा हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100 प्रतिशत सरकारी बजट समर्थनीय होगा।
3. तीन वर्ष की अवधि के लिए भारत सरकार का कुल अंश 2849.54 करोड़ रुपये होगा।

वासेनर का सदस्य बना भारत

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। **क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा उत्कृष्ट निर्यात नियंत्रण व्यवस्था देखनेवाली संस्था वासेनर अरेंजमेंट (डब्ल्यूए)** ने भारत को अपना नया सदस्य बनाया है। भारत के वासेनर अरेंजमेंट का 42वां सदस्य बनने से अप्रसार क्षेत्र में देश का कद बढ़ने के साथ महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को हासिल करने में भी मदद मिलेगी। साथ ही, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) के शामिल किए जाने का दावा मजबूत होगा। वासेनर का सदस्य बनने के बाद जहां एक तरफ भारत को महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी मिल पाएगी तो वहीं दूसरी तरफ परमाणु अप्रसार के क्षेत्र में एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं करने के बावजूद नई दिल्ली का रुतबा भी बढ़ेगा।

क्या है

1. भारत को वासेनर में शामिल करने का फैसला विना में चली दो दिनों की बैठक में लिया गया है। इससे परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) पर भारत का दावा और भी मजबूत होगा।
2. इसके सदस्य देशों के बीच हथियारों के हस्तांतरण में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाता है। चीन इस संस्था का सदस्य नहीं है, फिर भी उसने अड़चन डालने की भरसक कोशिश की।
3. वासेनर अरेंजमेंट में शामिल देशों ने सदस्यों के लिए आए आवेदनों की समीक्षा की और भारत को 42वें सदस्य देश के तौर पर शामिल करने पर सहमति बनी। जैसे ही इस दिशा में जरूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी भारत वासेनर का सदस्य बन जाएगा।
4. गौरतलब है कि पिछले साल जून में भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम (एमटीसीआर) की पूर्णकालिक सदस्यता दी गई थी।
5. इससे पहले भारत सरकार ने हाल ही में **SCOMET** (वासेनर अरेंजमेंट के तहत अनिवार्य स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिज्म, मटीरियल, इक्विपमेंट और टेक्नॉलजीज आइटम्स) को मंजूरी दी है। वस्तुओं की इस संशोधित सूची के जरिये भारत विश्व में अप्रसार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर सकता है।
6. पिछले वर्ष भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम (MTCR) समूह में शामिल हुआ था।
7. MTCR की व्यवस्था मिसाइल तकनीक व खतरनाक हथियारों के नियंत्रण से जुड़ी हुई है। MTCR में भारत के शामिल होने के बाद अब भारत अपनी ब्रह्मोस जैसी उच्च तकनीकी मिसाइलें मित्र देशों को बेच सकेगा। निकट भविष्य में ऑस्ट्रेलिया समूह में प्रवेश भारत के NSG में प्रवेश के प्रयास के बारे में कुछ देशों में संशय को समाप्त करने में मदद करेगा।

क्या है वासेनर अरेंजमेंट

1. इसकी स्थापना 1996 में वासेनर (नीदरलैंड) में की गई थी। यह परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम (MTCR) की तरह ही परमाणु अप्रसार की देखरेख करने वाली संस्था है।
2. वासेनर अरेंजमेंट सदस्य देशों के बीच परंपरागत हथियारों, दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।
3. इसके सदस्यों को यह सुनिश्चित करना होता है कि परमाणु प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण का दुरुपयोग न हो और इसका इस्तेमाल सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने में न किया जाए। इसका मुख्यालय विना में है।

अन्यगमन पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

अन्यगमन (एडल्टरी) के कृत्य में विवाहित महिला के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट इस सवाल पर सुनवाई करेगा। सर्वोच्च अदालत ने आईपीसी की एडल्टरी की धारा 497 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा **संविधान महिला और पुरुष दोनों को बराबर मानता है** तो आपराधिक केंसों में ये असमानता क्यों? कोर्ट ने कहा कि जीवन के हर पहलू में महिलाओं को पुरुषों के समान माना गया है तो इस मामले में अलग से बर्ताव कैसे हो रहा है। वह भी तब जब अपराध महिला और पुरुष दोनों की सहमति के साथ किया गया हो तो महिला को कानून से संरक्षण क्यों दिया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 15 (लिंग, धर्म और जाति के आधार पर बराबरी न देना) उल्लंघन लगता है।

क्या है

1. गौरतलब है कि आईपीसी की धारा 497 एक विवाहित महिला को संरक्षण देता है भले ही उसके दूसरे पुरुष से संबंध हों। इस कृत्य में महिला को पीड़ित ही माना जाता है, भले ही अपराध को महिला और पुरुष दोनों ने किया हो।
2. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रावधान की वैधता पर सुनवाई की जाएगी। किसी भी आपराधिक मामले में महिला के साथ अलग से बर्ताव नहीं किया जा सकता जब दूसरे अपराधों में लैंगिक भेदभाव नहीं होता तो इसमें क्यों।
3. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह भी अजीब है कि यह अपराध तब अपराध नहीं माना जाएगा जब इसके लिए पति स्वीकृति दे दे। सवाल यह है कि क्या महिला एक वस्तु है।
4. केरल के सामाजिक कार्यकर्ता जोसफ साइन ने वकील कालेश्वरम के जरिये दायर याचिका में धारा 497 की वैधता को चुनौती दी है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के तीन फैसलों (1954 और 1985) में इस धारा को वैध घोषित किया गया था और संसद को कानून में संशोधन करने की छूट दी गई थी। उन्होंने कहा कि संसद ने इस बारे में अब तक कुछ नहीं किया है।

क्या है धारा 497

1. जो भी व्यक्ति पति की सहमति या उसकी मिलीभगत के बिना उसकी स्त्री के साथ संबंध बनाता है तो यह रेप के समान नहीं होगा लेकिन वह एडल्टरी के अपराध का दोषी होगा।
2. ऐसे मामलों में पत्नी को उकसाने के कृत्य में ही दंडित किया जाएगा। धारा 497 के तहत दोषी करार दिए जाने पर दोषी को पांच साल तक की सजा और जुर्माना दोनों किए जा सकते हैं।
3. यह गैरजमानती और गैरमाफी योग्य है।

एनसीबीसी विधेयक को मंजूरी

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) को संवैधानिक हैसियत प्रदान करने संबंधी विधेयक को फिर से लोकसभा में पेश करने के लिए मंत्रिमंडल ने संशोधन को मंजूरी दे दी है। मंजूरी के बाद संसद के शीतकालीन सत्र में इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा। संसद से पारित होने के बाद एनसीबीसी के पास ओबीसी के अधिकार और हितों की सुरक्षा करने की पूरी शक्ति होगी। यह जानकारी सरकारी सूत्रों ने दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में संशोधन को मंजूरी दी गई। प्रस्तावित विधेयक को भाजपा द्वारा ओबीसी मतों को अपने पक्ष में करने के कदम के रूप में देखा जा रहा है। ओबीसी की सभी श्रेणियों की मांग को देखते हुए सरकार ने विधेयक पेश किया था।

क्या है

1. यह विधेयक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की तर्ज पर एनसीबीसी को भी संवैधानिक दर्जा देने के लिए लाया गया था।

2. प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक पहले लोकसभा में पेश और पारित किया गया। लेकिन राज्यसभा ने कुछ संशोधनों के साथ इसे पारित किया। इसके परिणामस्वरूप दोनों सदनों से अलग-अलग रूपों में विधेयक पारित हुआ। इसीलिए अब इसे फिर से लोकसभा में पेश किया जाएगा।
3. **एनसीबीसी 1993 में गठित एक वैधानिक निकाय है।** इसके पास सीमित शक्तियां हैं। आयोग केवल ओबीसी की केंद्रीय सूची में समुदाय को शामिल या हटाने के लिए सरकार से सिफारिश कर सकता है।

भारत की एक मात्र परमाणु पनडुब्बी क्षतिग्रस्त

भारतीय नौसेना की एक मात्र परमाणु पनडुब्बी 'आइएनएस चक्र' क्षतिग्रस्त हो गई है। नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने बताया कि घटना की बोर्ड ऑफ इन्क्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। 190 मेगावाट के परमाणु रिएक्टर वाली इस पनडुब्बी को रूस से 2012 में 10 साल की लीज पर लिया गया था। नौसेना दिवस (चार दिसंबर) से पहले पत्रकारों से बातचीत में एडमिरल लांबा ने बताया, 'पनडुब्बी के सोनार डोम्स को कुछ क्षति पहुंची है जहां उसके दो पैनेल उखड़ गए हैं।' उन्होंने कहा कि भारत और रूस के विशेषज्ञों का संयुक्त दल क्षति का आकलन करने के लिए पहले ही पनडुब्बी का परीक्षण कर चुका है। इसके अलावा नए पैनेलों का ऑर्डर भी दिया जा चुका है।

क्या है

1. एडमिरल लांबा ने उम्मीद जताई कि पनडुब्बी जल्द ही दुरुस्त हो जाएगी। उन्होंने रूसी मीडिया की उन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया कि भारतीय नौसेना ने अमेरिका के तकनीकी दल को पनडुब्बी की जांच करने की अनुमति दी थी।
2. एडमिरल लांबा ने साफ कहा कि किसी भी अमेरिकी अधिकारी ने इसे करीब से भी नहीं देखा है। 'आइएनएस चक्र' करीब ढाई महीने पहले क्षतिग्रस्त हुई थी।

डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर राष्ट्र को समर्पित

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने इस संस्थान की आधारशिला अप्रैल, 2015 में रखी थी। इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि डॉ. अंबेडकर की दृष्टि और शिक्षा के प्रसार में केंद्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस बात पर गौर करते हुए कि डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर फॉर सोसियो-इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन भी इस परियोजना का हिस्सा है, प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र होगा। उन्होंने कहा कि यह सेंटर समावेशी विकास एवं संबंधित सामाजिक-आर्थिक मामलों के लिए एक थिंक-टैंक (विचारक) के रूप में काम करेगा।

क्या है

1. प्रधानमंत्री ने कहा कि विचारकों एवं दूरदर्शी नेताओं ने समय-समय पर हमारे देश की दिशा निर्धारित की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में बाबा साहब के योगदान के लिए देश उनका ऋणी है।
2. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक लोगों और विशेष तौर पर युवाओं को उनकी दृष्टि और विचारों से अवगत कराया जाए। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि डॉ. अंबेडकर के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण जगहों को तीर्थस्थल के रूप में विकसित किया गया है।
3. इस संदर्भ में उन्होंने दिल्ली में अलीपुर, मध्य प्रदेश में महु, मुंबई में इंदु मिल, नागपुर में दीक्षा भूमि और लंदन में उनके मकान का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह पंचतीर्थ आज की पीढ़ी द्वारा डॉ. अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने का तरीका है। उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन के लिए भीम ऐप केंद्र सरकार द्वारा डॉ. अंबेडकर की आर्थिक दृष्टि को श्रद्धांजलि है।
4. दिसंबर, 1946 में संविधान सभा में डॉ. अंबेडकर के संबोधन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि तमाम संघर्षों के बावजूद राष्ट्र को उसकी समस्याओं से उबारने के लिए डॉ. अंबेडकर के पास एक प्रेरणादायक दृष्टिकोण था।

5. उन्होंने कहा कि हम अभी भी डॉ. अंबेडकर के दृष्टिकोण को पूरा नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी में सामाजिक बुराइयों को खत्म करने की क्षमता और ताकत मौजूद है।
6. प्रधानमंत्री ने डॉ. अंबेडकर के शब्दों को याद किया कि हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र के साथ-साथ एक सामाजिक लोकतंत्र का भी निर्माण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले तीन से साढ़े तीन वर्षों के दौरान केंद्र सरकार ने सामाजिक लोकतंत्र की उस दृष्टि को पूरा करने के लिए काम किया है। इस संदर्भ में उन्होंने जनधन योजना, उज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और हाल में शुरू की गई सौभाग्य योजना जैसे सरकारी कार्यक्रमों का उल्लेख किया।

यातना के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन

हाल ही में विधि आयोग द्वारा कहा गया है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र के यातना के विरुद्ध कन्वेंशन (UN Convention Against Torture) की पुष्टि कर देनी चाहिये। गौरतलब है कि दो दशक पहले इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कर चुका भारत अब तक इसकी पुष्टि नहीं कर पाया है।

क्या है

1. यातना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसकी घोषणा वर्ष 1984 में तथा इसे लागू वर्ष 1987 में किया गया।
2. इस कन्वेंशन को वर्तमान में 162 सदस्य अपनी सहमति दे चुके हैं, जबकि 83 पक्ष इसके हस्ताक्षरकर्ता हैं।
3. कन्वेंशन को स्वीकृति देने से इनकार करने वाले कुछ देश हैं- अंगोला, बहामा, ब्रुनेई, जाम्बिया, हैती और सूडान आदि। भारत भी इन देशों के साथ इस निंदनीय सूची का हिस्सा है।
4. इसका उद्देश्य दुनिया भर में होने वाली यातनाओं तथा क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक कृत्यों को रोकना है।
5. यह यातना देने को एक दंडनीय अपराध मानता है और पीड़ितों के लिये मुआवजे के अधिकार को मान्यता देता है।
6. यह देशों को अपने नागरिक, उन देशों में भेजने से मना करता है, जहाँ यह संभावना है कि उन्हें यातना झेलनी पड़ सकती है।

ई-कोर्ट परियोजना के बारे में राष्ट्रीय कान्फ्रेंस

भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-कमेटी ने भारत सरकार के न्याय विभाग के सहयोग से 2 और 3 दिसंबर को नई दिल्ली में दो दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जिसमें विभिन्न उच्च न्यायालयों के सभी केन्द्रीय परियोजना समन्वयकों, न्याय विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के वरिष्ठ अधिकारियों तथा कई अन्य वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन की अध्यक्षता ई-कमेटी के प्रभारी न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री मदन बी. लोकुर ने की और सहअध्यक्ष थे न्याय विभाग के सचिव डॉ. आलोक श्रीवास्तव। सम्मेलन में अब तक हुई प्रगति, बेहतरीन तौर-तरीकों और अनुभवों को साझा करने और परियोजना के अंतर्गत उभर कर आ रही नयी चुनौतियों पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को सूचना और संचार टेक्नोलाजी के जरिए सशक्त करके राष्ट्रीय ई-अभिशासन परियोजना के दायरे में लाने की मिशन मोड में चलाई जा रही परियोजना (प्रथम चरण 2010-15 और द्वितीय चरण 2015-19) है।

परियोजना के प्रमुख उद्देश्य हैं

1. समूची न्यायिक प्रणाली को सूचना और संचार टेक्नोलाजी से समन्वित करने के लिए पर्याप्त और आधुनिक हार्डवेयर व सम्पर्क कायम करना
2. सभी न्यायालयों में कामकाज के आने और निपटाने की प्रक्रिया के प्रबंधन का ऑटोमेशन करना

3. तालुका/निचली अदालतों के रिकार्ड का अपील कोर्टों से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से स्थानांतरण
4. वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा की स्थापना और इसके जरिए गवाहों के बयान दर्ज करना
5. देश की सभी अदालतों को राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) से वाइड एरिया नेटवर्क (वैन) के जरिए जोड़ना और अन्य संपर्क
6. इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग जैसी सुविधाओं के माध्यम से नागरिक केंद्रित सुविधाएं
7. हर न्यायालय परिसर में टच स्क्रीन आधारित क्योस्क की स्थापना
8. राज्य और जिला स्तर की न्यायिक और सेवा अकादमियों व केन्द्रों का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण
9. परियोजना के तहत नियत किये गये विशिष्ट लक्ष्यों में सभी न्यायालयों (करीब 20400) और जिला विधि सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) और तालुका न्यायिक सेवा कमेटी (टीएलएससी) का कम्प्यूटरीकरण और 3500 अदालत परिसरों के बीच क्लाउड कनेक्टिविटी कायम करना
10. 3000 न्यायालय परिसरों और 1150 कारागारों में वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा की स्थापना और उसका उपयोग
11. इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, दैनिक आदेश, आदेशों के वितरण, सभी जिला अदालतों में मामलों की ऑनलाइन स्थिति का पता लगाने की सुविधा आदि की स्थापना

कलवरी से बढ़ी ताकत

भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट -75 के तहत माइगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) द्वारा तैयार की गई देश की पहली स्कार्पिन क्लास पनडुब्बी को 14 दिसम्बर को देश को समर्पित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश को समर्पित किया। इस पनडुब्बी से देश की नौसेना की ताकत काफी बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि चीन ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी नौसैनिक क्षमता में काफी बढ़ोत्तरी की है। चीन की तरफ से देश में बनाई गई सबसे ताकतवर पनडुब्बी और नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च किया जा चुका है। इसके अलावा भी वह अपनी समुद्री ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत के पास स्कार्पिन क्लास की अत्याधुनिक पनडुब्बी का होना काफी मायने रखता है। इसके जरिए भारत हिंद महासागर क्षेत्र में चीन को चुनौती देने में और सक्षम हो जाएगा।

क्या है

1. सबमरीन के निर्माण के प्रोग्राम को प्रोजेक्ट-75 नाम दिया गया था, जो कि तीस वर्षों की प्लानिंग थी, जिसे साल 1999 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिव्योरिटी ने इजाजत दी थी।
2. दो प्रोडक्शन लाइन प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75 (I) के तहत छह-छह सबमरीन का निर्माण किया जाना है। इसके साथ ही 12 कन्वेंशनल सबमरीन को बनाया जाना है। मतलब वर्ष 2030 तक नौसेना के पास कुल 24 आधुनिक सबमरीन होंगी। ऐसे में नौसेना की शक्ति में अगले कुछ वर्षों में खासी बढ़ोत्तरी होगी, जिससे हिंद महासागर में दुश्मनों पर नजर रखी जा सकेगी।
3. स्कार्पिन क्लास की कुल छह पनडुब्बियों का निर्माण माइगाव डॉक लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। एमडीएल ने इस पनडुब्बी को 21 सितंबर 2017 को नौसेना को सौंपा था।
4. स्कार्पिन सीरीज की दूसरी सबमरीन का निर्माण जारी है, खांडेरी सबमरीन का समुद्र में परीक्षण किया जा रहा है। इसका निर्माण कार्य इस वर्ष जनवरी में शुरू हुआ था। तीसरी सबमरीन कारांज का लांच अगले वर्ष हो सकेगा। भारत और फ्रांस के बीच छह सबमरीन का निर्माण कार्य और तकनीक ट्रांसफर को लेकर वर्ष 2005 में समझौता हुआ था।

आधार डेडलाइन पर सुप्रीम कोर्ट राजी

आधार पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला आया है। सभी योजनाओं को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च करने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। सर्वोच्च अदालत की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने यह अंतरिम आदेश दिया। इसके साथ ही मोबाइल फोन के साथ आधार को लिंक करने की

अवधि भी बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार के बिना भी बैंक में नया खाता खुलवाया जा सकता है लेकिन आवेदक को इस बात का सबूत देना होगा कि उसने आधार कार्ड के लिए आवेदन दिया है। मोबाइल सेवाओं को आधार से जोड़ने की छह फरवरी की समयसीमा को भी 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वह मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च 2018 करने के लिए तैयार है। उसने पहले ही दूसरी सर्विसेज के लिए डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है।

क्या है

1. अब चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पांच जजों की बेंच ने इस मामले में अंतरिम आदेश दिया है, जो जनवरी में आधार कानून की वैधानिकता पर सुनवाई पूरी होने तक लागू रहेगा।
2. गौरतलब है कि एक अलग मामले में आधार कानून की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। देश की सबसे बड़ी अदालत में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि जब आधार कानून की वैधानिकता पर सुनवाई चल रही है, तब सरकार बायोमीट्रिक आईडी की अनिवार्य लिंकिंग की बात कैसे कर सकती है? याचिका में इस पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई है।
3. आधार लिंकिंग के खिलाफ मुहिम की अगुवाई करते हुए सीनियर वकील श्याम दीवान ने कहा है कि नए कानून कोर्ट के पहले के आदेश को ओवररूल नहीं कर सकते, जिनमें कहा गया था कि आधार का सिर्फ स्वैच्छिक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए दबाव नहीं डाला जा सकता।
4. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार का इस्तेमाल 6 स्कीम में सिर्फ पहचान के लिए किया जा सकता है। दीवान ने कहा कि उसके बावजूद केंद्र और राज्यों ने सर्कुलर और नोटिस के जरिए कई चीजों के लिए इसे अनिवार्य बना दिया है।
5. इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नए कानून की वजह से सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश निरस्त हो जाते हैं। उन्होंने दावा किया, 'अगर एक कानून बनाया जाता है तो वह अपने आप में मुकम्मल होता है।'

ट्रिपल तलाक पर कैबिनेट से मिली हरी झंडी

मोदी सरकार ने अहम फैसला लेते हुए कैबिनेट में ट्रिपल तलाक विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब इस बिल को संसद की मंजूरी के लिए दोनों सदन में रखा जाएगा। यह कानून मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) से राहत दिलाएगा। 'द मुस्लिम वूमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन मैरिज एक्ट' के नाम वाला यह विधेयक केंद्र सरकार की ओर से तैयार किया गया है। जिसमें कहा गया है कि एक बार में तीन तलाक गैरकानूनी होगा और ऐसा करने वाले को तीन साल जेल की सजा हो सकती है। किसी भी स्वरूप में दिया गया ट्रिपल तलाक (मौखिक, लिखित या इलैक्ट्रॉनिक) गैर कानूनी माना जाएगा।

बिल में क्या हैं प्रावधान

1. प्रस्तावित बिल के मुताबिक तीन साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही यह गैरजमानती अपराध होगा।
2. अगर कोई पति अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक देता है तो उसे तीन साल की सजा हो सकती है और इस दौरान उसे जमानत भी नहीं मिलेगी।
3. 'मुस्लिम वूमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल' प्रस्तावित कानून में पीड़िता को अपने पति से हर्जाना मांगने का भी अधिकार होगा। इसके साथ ही वह अपने बच्चे की कस्टडी की मांग भी कर सकती है। यह कानून केवल एक साथ तीन तलाक देने पर लागू होगा।

क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने

1. सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुसलमानों में 1400 वर्षों से प्रचलित एक बार में तीन तलाक यानी तलाक-ए-बिद्दत को असंवैधानिक करार देकर निरस्त कर दिया था।
2. कोर्ट ने तीन-दो के बहुमत से फैसला देते हुए कहा था कि एक साथ तीन तलाक संविधान में दिए गए बराबरी के अधिकार का हनन है।
3. तलाक-ए-बिद्दत इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है। इसलिए इसे धार्मिक आजादी के तहत संरक्षण नहीं मिल सकता।

4. इस बिल का ड्राफ्ट केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाले अंतर मंत्री समूह ने बनाया है। राजनाथ के अलावा इस समूह में वित्त मंत्री अरुण जेटली, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और कानून राज्यमंत्री पीपी चौधरी भी शामिल थे।

‘सामाजिक अंकेक्षण’ को आधिकारिक दर्जा

मेघालय सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के सामाजिक अंकेक्षण को सरकारी काम-काज का हिस्सा बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार ने हाल ही में ‘मेघालय सामुदायिक भागीदारी एवं लोक सेवा सामाजिक अंकेक्षण अधिनियम 2017’ लागू किया है।

क्या है

1. यह अधिनियम राज्य के 11 सरकारी विभागों और 21 योजनाओं पर लागू किया गया है। हालाँकि शुरुआत के तौर पर 18 गाँवों की 26 योजनाओं को इसमें शामिल कर लिया गया।
2. मेघालय का कार्यक्रम कार्यान्वयन और मूल्यांकन विभाग इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिये नोडल एजेंसी है।
3. सामाजिक अंकेक्षण अब तक सिविल सोसाइटी की पहल पर किये जाते रहे हैं और इन्हें कोई आधिकारिक दर्जा हासिल नहीं था।
4. यह देश में पहली बार है कि किसी राज्य ने सामाजिक अंकेक्षण को सरकारी तंत्र में आधिकारिक तौर पर शामिल किया है।

क्या होता है सामाजिक अंकेक्षण?

1. सामाजिक लेखा या सामाजिक अंकेक्षण किसी भी कार्यक्रम अथवा क्रिया, जिसका संबंध प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से समाज से होता है, के सामाजिक निष्पादन के मूल्यांकन से संबंधित प्रक्रिया है।
2. इसका प्रयोग किसी कार्य के प्राथमिक स्तर अर्थात् उद्भव से लेकर क्रियान्वयन एवं उस क्रियान्वयन के दीर्घकाल तक के प्रभावों की स्वतंत्र व निष्पक्ष जाँच और उस जाँच में परिलक्षित कमियों में सुधार का परीक्षण, औचित्यता के साथ किया जाता है, ताकि समाज के हित में हर स्तर तक विकास हो सके।

राष्ट्रीय ट्रेकोमा सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी नड्डा ने राष्ट्रीय ट्रेकोमा सर्वेक्षण रिपोर्ट (2014-17) जारी की। उन्होंने घोषणा की कि भारत अब ‘रोग पैदा करने वाले ट्रेकोमा’ से मुक्त हो गया है और उन्होंने इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। श्री नड्डा ने कहा कि सर्वेक्षण के निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि सर्वेक्षण के सभी जिलों में बच्चों में ट्रेकोमा संक्रमण समाप्त हो चुका है और इसकी मौजूदगी केवल 0.7 प्रतिशत है। यह डब्ल्यूएचओ द्वारा परिभाषित ट्रेकोमा की समाप्ति के मानक से बहुत कम है। उन्होंने कहा कि ट्रेकोमा को उस स्थिति में समाप्त माना जाता है, यदि उसके सक्रिय संक्रमण की मौजूदगी 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में 5 प्रतिशत से कम हो। सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करने के अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल भी मौजूद थीं। स्वास्थ्य मंत्रियों ने सर्वेक्षण से जुड़े सभी लोगों, खासतौर से स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी, जिन्होंने सर्वेक्षण करने के लिए कठिन परिस्थितियों में भी कार्य किया।

क्या है

1. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सर्वेक्षण के परिणामों से संकेत मिलता है कि भारत में अब सक्रिय ट्रेकोमा जन स्वास्थ्य समस्या नहीं रह गई है।
2. हमने डब्ल्यूएचओ के जीईटी 2020 कार्यक्रम के अंतर्गत निर्दिष्ट लक्ष्य के अनुसार ट्रेकोमा का सफाया करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। यह कई दशकों के प्रयासों के बाद संभव हुआ है, जिनमें एंटीबायोटिक आईड्रॉप का प्रावधान, निजी सफाई, सुरक्षित जल की उपलब्धता, पर्यावरण संबंधी बेहतर स्वच्छता, क्रोनिक ट्रेकोमा के लिए सर्जिकल सुविधाओं की उपलब्धता और देश में सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सामान्य सुधार शामिल हैं।

3. हमारा लक्ष्य देश से ट्रेकोमेट्सस्ट्रीचियासिस को समाप्त करना है। ऐसे राज्य जो अभी भी सक्रिय ट्रेकोमा के मामलों की जानकारी दे रहे हैं, उन्हें ट्रेकोमेट्सस्ट्रीचियासिस के मरीजों के समुदाय आधारित निष्कर्षों को प्राप्त करने के लिए एक रणनीति विकसित करने की जरूरत है।
4. ऐसे मामलों की स्थानीय अस्पतालों में मुफ्त एंट्रोपियन सर्जरी/इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि ऐसे पहचाने गये प्रत्येक मामले को सावधानी से दर्ज किया जाना चाहिए और इसके प्रबंधन की स्थिति का डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देशों के अनुसार रखरखाव किया जाए। साथ ही भारत को ट्रेकोमा मुक्त प्रमाणित करने के लिए देश भर में इस बीमारी की पर्याप्त निगरानी की जानी चाहिए। डब्ल्यूएचओ के दिशा निर्देशों के अनुसार ट्रेकोमा निगरानी के संकेतों पर मासिक आंकड़े नियमित रूप से एनपीसीबी को भेजे जाएं।
5. ट्रेकोमा (रोहे-कुक्करे) आंखों का दीर्घकालिक संक्रमण रोग है और इससे दुनिया भर में अंधेपन के मामले सामने आते हैं। यह खराब पर्यावरण और निजी स्वच्छता के अभाव तथा पर्याप्त पानी नहीं मिलने के कारण होने वाली बीमारी है। यह आंखों की पलकों के नीचे झिल्ली को प्रभावित करता है। बार-बार संक्रमण होने पर आंखों की पलकों पर घाव होने लगते हैं, इससे कोर्निया को नुकसान पहुंचता है और अंधापन होने का खतरा पैदा हो जाता है।
6. इससे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश और निकोबार द्वीप के कुछ स्थानों के लोग प्रभावित पाए गए हैं। ट्रेकोमा संक्रमण 1950 में भारत में अंधेपन का सबसे महत्वपूर्ण कारण था और गुजरात, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश में 50 प्रतिशत आबादी इससे प्रभावित थी।
7. राष्ट्रीय ट्रेकोमा प्रचार सर्वेक्षण और ट्रेकोमा रैपिड असेसमेंट सर्वेक्षण डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सेंटर फॉर ऑपथेलमिक साइंस, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली ने 2014 से 2017 तक नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट के सहयोग से किया।
8. सर्वेक्षण 23 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के 27 सबसे अधिक जोखिम वाले जिलों में किया गया।

भू-जल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

देश में भू-जल के मुद्दे पर 11 से 13 दिसंबर, 2017 तक एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शीर्षक है 'भू-जल विज्ञान 2030-जल सुरक्षा, चुनौतियां और जलवायु परिवर्तन अनुकूलता'। सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी संस्थान (एनआईएच), रूड़की और केन्द्रीय भू-जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के तत्वाधान में किया जा रहा है।

क्या है

1. सम्मेलन में 15 देशों के प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है और 250 शोध पत्र प्रस्तुत किये जाएंगे, जिनमें 32 मुख्य सिद्धांत पर आधारित पत्र होंगे।
2. सम्मेलन में देश में पानी के इस्तेमाल और बदलते जलवायु परिदृश्य के अंतर्गत भू-जल की वर्तमान स्थिति और उसके प्रबंधन की चुनौतियों का जायजा लिया जाएगा।
3. सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है, जब देश में पानी का परिदृश्य, खासतौर से भू-जल परिदृश्य दिनों दिन बदल रहा है। पिछले दशकों के दौरान देश में भू-जल का इस्तेमाल कई गुना बढ़ा है और आज गांवों में 80 प्रतिशत घरेलू जरूरतें, सिंचाई के पानी की 65 प्रतिशत जरूरतें, औद्योगिक एवं शहर की 50 प्रतिशत जल की जरूरतों का स्रोत हमारे भू-जल संसाधन हैं।
4. भू-जल के दोहन से पंजाब, बुंदेलखंड और राजस्थान सहित देश के अन्य प्रमुख क्षेत्रों में कृषि कार्यों के लिए खतरा पैदा हो रहा है, जिससे भविष्य में खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। साथ ही भारी वर्षा होने की स्थिति में देश में भू-जल के फिर से भरने की स्थिति में बदलाव आ सकता है।
5. भू-जल के अत्याधिक दोहन के कारण अनेक इलाकों में भू-जल की गुणवत्ता प्रभावित होने लगी है और इसमें आर्सेनिक जैसे तत्व पाए जाने लगे हैं। सम्मेलन में इन ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होगी।

6. सम्मेलन में देश में जल संसाधनों से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के बीच सहक्रियाशील नीति विकल्पों पर भी गौर किया जाएगा और 2030 के विकास लक्ष्यों के लिए चुनौतियों को दूर करने के संबंध में एक रोड मैप तैयार किया जाएगा।

रेरा की वैधता को बरकरार रखा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम (आरईआरए) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। कोर्ट का मानना है कि फ्लैट खरीदारों के हितों की रक्षा करना और अधूरी परियोजनाओं को विकसित करना महत्वपूर्ण है। यह देखते हुए कि आवासीय क्षेत्र में 'बड़ी समस्याएं' हैं अदालत ने यह भी कहा कि अब महात्मा गांधी के प्रत्येक आंख से हर आंसू पोंछने की विचारधारा को पूरा करने के लिए एक कदम आगे जाने का समय है।

क्या है

1. अदालत ने इस अधिनियम के कार्यान्वयन के मुद्दे पर भी गौर किया और कहा कि इस पर बारीक नजर रखी जानी चाहिए।
2. जस्टिस नरेश पाटिल व जस्टिस राजेश केतकर की पीठ ने रियल एस्टेट डेवलपर्स और कुछ प्लॉट मालिकों की ओर से दायर विभिन्न याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। इन याचिकाओं में रेरा की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी, जिसे इस साल मई में लागू किया जा चुका है।
3. हालांकि, न्यायमूर्ति पाटिल की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने फैसले में डेवलपर को थोड़ी छूट दी है। अदालत ने कहा है कि राज्य स्तर के रेरा प्राधिकरण और अपीलीय ट्रिब्यूनल परियोजनाओं में देरी को मामले दर मामले आधार पर ही देखा जाएगा और ऐसी परियोजनाओं या डेवलपर्स के पंजीकरण को रद्द नहीं किया जाएगा जिसमें परियोजनाओं में देरी का कारण असाधारण परिस्थितितजन्य होगा।

यरुशलम को इजरायल की राजधानी माना

अमेरिका ने यरुशलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता देने का फैसला कर लिया है। वह अपने दूतावास को तेलअवीव से यरुशलम में स्थानांतरित कर देगा। अमेरिका के इस कदम को उसकी 70 साल पुरानी विदेश नीति से उलट देखा जा रहा है। अमेरिकी नीति के अनुसार यरुशलम का भविष्य इजरायल और फिलिस्तीन को बातचीत के जरिये तय करना था।

क्या है

1. यरुशलम की आबादी 8.82 लाख है। शहर में 64 फीसद यहूदी, 35 फीसद अरबी और एक फीसद अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। शहर का क्षेत्रफल 125.156 वर्ग किमी है।
2. इजरायल और फिलिस्तीन, दोनों ही अपनी राजधानी यरुशलम को बनाना चाहते थे। इस ऐतिहासिक शहर में मुस्लिम, यहूदी और ईसाई समुदाय की धार्मिक मान्यताओं से जुड़े प्राचीन स्थल हैं।
3. 1980 में इजरायल ने यरुशलम को राजधानी घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव पारित कर पूर्वी यरुशलम पर इजरायल के कब्जा की निंदा की और इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। 1980 से पहले यरुशलम में नीदरलैंड और कोस्टा रिका जैसे देशों के दूतावास थे। लेकिन 2006 तक देशों ने अपना दूतावास तेलअवीव स्थानांतरित कर दिया। अंतरराष्ट्रीय समुदाय यरुशलम पर इजरायल के आधिपत्य का विरोध करता आया है लिहाजा तेलअवीव में ही सभी 86 देशों के दूतावास हैं।
4. 1947 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा यरुशलम के विभाजन का प्लान रेखांकित किया गया था। इसका मकसद यरुशलम को अलग अंतरराष्ट्रीय शहर के रूप में परिकल्पित करना था।
5. 1948 में इजरायल के आजाद होने पर शहर का विभाजन हुआ। 1949 में युद्ध समाप्त होने पर आर्मिटाइस सीमा खींची गई। इससे शहर का पश्चिमी हिस्सा इजरायल और पूर्वी हिस्सा जॉर्डन के हिस्से आया।

6. 1967 में हुए छह दिनी युद्ध में इजरायल ने जॉर्डन से पूर्वी हिस्सा भी जीत लिया। शहर को इजरायली प्रशासन चला रहा है। लेकिन फिलिस्तीन पूर्वी यरुशलम को भविष्य की अपनी राजधानी के रूप में देखता है।
7. अमेरिकी दूतावास को तेलअवीव से यरुशलम में स्थानांतरित करने के लिए 1995 में अमेरिकी कांग्रेस में कानून पारित हुआ। इजरायल ने नए दूतावास के लिए 99 साल के लिए एक डॉलर सालाना किराये पर अमेरिका को यरुशलम में जमीन भी उपलब्ध कराई। लेकिन 1995 के बाद से सभी अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर इसे टालते रहे। इसके लिए वे प्रत्येक छह महीने में एक अधित्याग पत्र पारित करते हैं।

कापू आरक्षण विधेयक को मिली मंजूरी

आंध्रप्रदेश में ताकतवर माने जाने वाले कापू समुदाय के लिए विधानसभा में पेश आरक्षण विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। अब इसे केंद्र में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। इससे पहले राज्य सरकार ने कापू समुदाय को शिक्षा और रोजगार में पांच फीसद आरक्षण देने का फैसला किया था। अब कापू समुदाय को अब एक नई कैटगरी बीसी (एफ) बनाकर अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाएगा।

क्या है

1. मनजुनाथा आयोग के द्वारा की गई सिफारिशों पर सहमति के बाद कापू समुदाय को आरक्षण देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य विधानसभा में बिल पेश किया।
2. राज्य में शासित तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने 2014 के चुनावी वादों को पूरा करने के लिए यह फैसला लिया, लेकिन लागू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तय की हुई 50 फीसद आरक्षण की सीमा को पार कर जाएगा।
3. कापू समुदाय पिछले तीन दशकों से आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं। कापू के अंदर तेलगा, बालिजा और ओंटारी समुदाय आते हैं।
4. अब तक राज्य में ओबीसी को ए, बी, सी, डी और ई कैटगरी के तहत 25% तक के आरक्षण का लाभ मिल रहा था। कापू समुदाय को 5% आरक्षण मिल जाने के बाद ओबीसी आरक्षण 30 फीसद पहुंच जाएगा।

बौधि पर्व का उद्घाटन

संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. महेश शर्मा ने वर्तमान समय में भगवान बुद्ध के शांति और सद्भाव के संदेश को प्रासंगिक बताते हुए कहा कि इन संदेशों ने विभिन्न देशों को एक सूत्र में पिरोया है। डॉ. शर्मा दिसम्बर 08, 2017 को नई दिल्ली में बौधि पर्व: बौद्ध विरासत के समृद्ध उत्सव का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ढाई सहस्राब्दी पहले दिए गए महात्मा बुद्ध के संदेश आज भी प्रासंगिक है और यह विभिन्न देशों के बीच एक कड़ी के रूप में विद्यमान है। उन्होंने कहा कि शांति, समग्रता और प्रेम व स्नेह के नैतिक मूल्य हमारे समाज में विद्यमान है और इन पर महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रभाव है। डॉ. महेश शर्मा ने कहा कि बौधि पर्व के अंतर्गत बौद्ध विरासत की घनिष्ठ परंपरा दर्शायी गई है इस दौरान भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध कलाओं और वास्तु की प्रदर्शनी, विशिष्ट शिक्षाविदों और बौद्ध धर्म के अनुयायी के बीच संवाद, बौद्ध संयासियों द्वारा बौद्ध धर्म के संदेशों का पाठ और चिंतन, बौद्ध धर्म पर फिल्मों का प्रदर्शन, नृत्य एवं संगीत, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं एवं खानपान के स्टॉल भी लगाए गए हैं। इससे बिमस्टेक देशों की समृद्ध और समान परंपरा के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

क्या है

1. इस क्षेत्रीय संगठन में बंगाल की खाड़ी के आसपास के सात सदस्य देश शामिल हैं जो एकता के बंधन में बंधे हैं। बिमस्टेक देशों ने इस क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2. पूरे विश्व की आबादी का पांचवे हिस्से के बराबर इन देशों की संयुक्त रूप से जीडीपी 2 दशमलव 8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है।

3. अक्तूबर, 2016 में गोवा में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आयोजित इन देशों के नेताओं के सम्मेलन में इस दिशा को और अधिक गति हासिल हुई है।
4. सदस्य देशों के बीच संपर्क, व्यापार, लोगों के बीच आपसी संपर्क और संसाधनों के अधिकाधिक इस्तेमाल पर सहमति बनी है और इस पर तेजी से कार्यान्वयन हो रहा है।
5. **भारत बिमस्टेक को अपनी विदेश नीति की प्राथमिकताओं नेबरहुड फस्ट और एक्ट ईस्ट की पूर्णता के लिए एक नैसर्गिक प्लेटफॉर्म के रूप में देख रहा है।** उन्होंने बताया कि सुरक्षा, यातायात एवं संचार, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन, पर्यटन, पारंपरिक औषधियों एवं लोगों के बीच आपसी संपर्क के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि **‘बौद्धि पर्व’ जैसे उत्सवों से बाण्ड बिमस्टेक के संबद्धन में बहुत मदद मिलेगी।**
6. बौद्धि पर्व के उद्घाटन समारोह में नेपाल के संस्कृति, पर्यटन एवं नागरिक विमानन मंत्री श्री जितेन्द्र नारायण देव, विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीमती प्रीति शरण, बंगलादेश के संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री इब्राहिम हुसैन खान, बिमस्टेक सदस्य देशों के मिशनों के प्रमुख, तथा भारत एवं अन्य बिमस्टेक सदस्य देशों के कलाकार एवं विद्वान भी शामिल थे।
7. **बिमस्टेक की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर विभिन्न समारोहों के एक भाग के रूप में 8 से 10 दिसम्बर को बौद्धि पर्व बौद्ध विरासत के समृद्ध उत्सव का आयोजन किया गया है।**

अन्तरराष्ट्रीय

भारत और जर्मनी ने अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर

भारत और जर्मनी ने ‘पर्यावरण अनुकूल शहरी गतिशीलता III’ परियोजना के लिए ऋण के रूप में वित्तीय सहायता के लिए 200 मिलियन यूरो तक की राशि और चार परियोजनाओं के लिए अनुदान के रूप में 11 मिलियन यूरो के संलग्न उपायों को औपचारिक रूप देने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। समझौते पर जर्मनी की ओर से भारत में जर्मनी के राजदूत डॉ. मार्टिन नेय और भारत की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव श्री एस. सेल्वाकुमार ने हस्ताक्षर किए। समझौते के भाग-1 में मई, 2017 में हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इसके अलावा भारत-जर्मन द्विपक्षीय विकास सहयोग के अंतर्गत दोनों देशों के बीच निम्नलिखित ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए:-

1. **“समुदाय आधारित सतत वन प्रबंधन- घटक I मणिपुर”** के लिए 15 मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना का विस्तृत उद्देश्य जल ग्रहण करने वाले ऊपरी क्षेत्रों में नष्ट हो चुके जंगलों को बहाल करना, छोड़े गए कृषि क्षेत्रों में भूमि सुधार, जैव विविधता संरक्षण, जल संसाधन संरक्षण और परियोजना वाले क्षेत्र में वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातीय लोगों की आजीविका में सुधार करना है।
2. **“मध्य प्रदेश शहरी स्वच्छता और पर्यावरण कार्यक्रम”** परियोजना के लिए कम ब्याज दर पर 50 मिलियन यूरो के ऋण और 2.5 मिलियन यूरो के अनुदान का समझौता किया गया। इस परियोजना का विस्तृत उद्देश्य मध्य प्रदेश के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति, स्वच्छता और सीवरेज शोधन संयंत्र की सुविधा में सुधार और कुछ शहरों में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन और उसके निपटारे की प्रणाली में सुधार, बाढ़ के पानी को कम करने के लिए जमीनी निकासी प्रणाली में सुधार करना है।
3. **“निरंतर शहरी बुनियादी ढांचा विकास ओडिशा-चरण II”** परियोजना के लिए कम ब्याज दर पर 55 मिलियन यूरो के ऋण और 2 मिलियन यूरो के अनुदान का समझौता किया गया। इस परियोजना का मूल उद्देश्य शहरी बुनियादी ढांचे को सरकार की प्राथमिकताओं से जोड़कर उनमें सुधार करना है। परियोजना का विस्तृत उद्देश्य ओडिशा में शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार करना और लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करना है।
4. **“महाराष्ट्र में हरित ऊर्जा गलियारा- अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली”** परियोजना के लिए कम ब्याज दर पर 12 मिलियन यूरो के ऋण का समझौता किया गया। परियोजना का विस्तृत उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा ले जाने के लिए पारेषण प्रणाली स्थापित करना है।

भारत और क्यूबा के बीच समझौता पत्र

भारत और क्यूबा के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे पी नड्डा एवं क्यूबा के स्वास्थ्य मंत्री डॉ रोबर्टो टोमस मोरलस ओजेदा ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और क्यूबा का एक प्रतिनिधि मंडल भी उपस्थित था।

क्या है

1. समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए श्री जे पी नड्डा ने कहा कि भारत और क्यूबा के बीच साझा समानता के मूल्यों और न्याय पर आधारित ऐतिहासिक संबंध हैं। दोनों ही देश कई वैश्विक मुद्दों पर समान राय रखते हैं।
2. श्री नड्डा ने कहा कि स्वास्थ्य एवं दवाईयों के क्षेत्र में सहयोग के लिए यह समझौता बेहद महत्वपूर्ण है। इससे दोनों ही देशों के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में संस्थागत सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
3. फार्मा और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं। क्यूबा ने बायोटेक्नोलॉजी और फार्मा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। हमें संयुक्त रूप से व्यापारिक स्तर पर दवाईयों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत सहयोग को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। श्री नड्डा ने कहा कि उन्होंने समझौते को लागू करने के लिए एक संयुक्त कार्य दल के गठन का सुझाव दिया है।

मिसाइल-ट्रैकिंग अभ्यास शुरू हुआ

परमाणु हथियार सम्पन्न उत्तर कोरिया द्वारा अंतरमहाद्वीपीय मारक क्षमता वाले मिसाइल परीक्षण के बाद अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने उत्तर कोरिया से दागी जाने वाली मिसाइलों का पता लगाने के लिए एक संयुक्त मिसाइल ट्रैकिंग अभ्यास शुरू किया है। दक्षिण कोरिया की सेना ने यह जानकारी दी। तीनों देशों के इस अभ्यास से महज दो सप्ताह से भी कम समय पहले उत्तर कोरिया ने एक नये अंतर-महाद्वीपीय बलिस्टिक मिसाइल (आईसीबीएम) का प्रायोगिक परीक्षण करके घोषणा की कि उसने परमाणु शक्ति सम्पन्न देश का दर्जा हासिल कर लिया है। उत्तर कोरिया द्वारा अपने हथियारों के जखीरे में वृद्धि करने से वैश्विक चिंता बढ़ा दी है। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दो दिन का यह अभ्यास कोरियाई प्रायद्वीप एवं जापान के निकट स्थित समुद्र में शुरू किया गया।

क्या है

1. पिछले साल जून में इसी तरह का अभ्यास सम्पन्न हुआ था जिसके बाद इस तरह का यह छठा अभ्यास है।
2. इस अभ्यास में तीनों देशों के एक-एक युद्धक पोत शामिल हैं जो दुश्मन की मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता रखते हैं।
3. यह उत्तर कोरिया की ओर से आने वाले संभावित बलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाने के लिए अभ्यास करेंगे और सूचनाएं साझा करेंगे।
4. दोनों एशियाई देशों से एक-एक जहाज और अमेरिका से दो जहाज इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं।

वेनेजुएला की नई क्रिप्टोकॉरेंसी: 'पेट्रो'

वेनेजुएला ने 'पेट्रो' नामक अपनी एक नई आभासी मुद्रा (वर्चुअल करेंसी) जारी करने की घोषणा की है। इस नई मुद्रा का उपयोग वेनेजुएला के तेल, गैस, सोना और हीरा उद्योग कर सकेंगे।

'पेट्रो' जारी करने के कारण

1. वेनेजुएला पर लगभग 9 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज है।
2. वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था हमेशा से ही यहाँ के तेल-संसाधनों पर निर्भर रही है, लेकिन तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट के चलते इसे आर्थिक और राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।

3. अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण भी यहाँ की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है।
4. तेल राजस्व में कमी के साथ-साथ वेनेजुएला की मुद्रा बोलिवर में लगातार हो रही गिरावट ने भी आर्थिक चुनौतियाँ उत्पन्न कर दी थीं। पिछले 4-5 सप्ताह में ही बोलिवर में 57% की गिरावट हुई है।
5. वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन की बढ़ती लोकप्रियता भी इसका एक कारण है।
6. यह उम्मीद की जा रही है कि नई मुद्रा वेनेजुएला को लेन-देन में रुकावटों से निपटने तथा आर्थिक स्थिरता लाने में मदद करेगी।

पृष्ठभूमि

1. पेट्रो एक प्रकार की क्रिप्टोकॉरेसी है।
2. क्रिप्टोकॉरेसी को डिजिटल करेंसी, वर्चुअल करेंसी, इंटरनेट करेंसी, ई-करेंसी या पीपुल्स-करेंसी भी कहा जाता है।
3. इस मुद्रा के उपयोग और भुगतान के लिये क्रिप्टोग्राफी नामक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है।
4. विश्व की पहली क्रिप्टोकॉरेसी बिटकॉइन है।
5. क्रिप्टोकॉरेसी को कहीं भी आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है तथा किसी अन्य मुद्रा जैसे- डॉलर, यूरो आदि में भी आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है।
6. क्रिप्टोकॉरेसी से कुछ जोखिम भी जुड़े हुए हैं। यह बेहद उछाल और गिरावट वाली मुद्रा है। बिटकॉइन की चोरी या घोटाले जैसी खबरों से ही इसकी कीमतों में गिरावट आ जाती है।
7. इसे खरीदने और बेचने वालों का एक-दूसरे से अपरिचित होना भी एक प्रकार का जोखिम है।
8. क्रिप्टोकॉरेसी का कोई नियामक प्राधिकरण नहीं है। धोखाधड़ी होने की स्थिति में ऐसा कोई प्राधिकारी नहीं है, जिसके समक्ष इसकी शिकायत लेकर जाया जा सके।

ब्रेजिट विधेयक औंधे मुंह गिरा

ब्रिटेन सरकार को ब्रेजिट विधेयक पर संसद में हार का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री टरीजा की सरकार के 11 सांसदों की बगावत के बाद यह विधेयक संसद में औंधे मुंह गिर गया। प्रधानमंत्री टरीजा को झटका देते हुए सांसदों ने इस विधेयक में संशोधन के पक्ष में वोट किया। सरकार इससे पहले तर्क दे चुकी है कि इस विधेयक में संशोधन से यूरोपीय संघ (ईयू) से ब्रिटेन के निकलने में बाधा उत्पन्न होगी।

क्या है

1. विद्रोहियों को राहत देने के आखिरी मिनट के प्रयास के बावजूद विधेयक में संशोधन के पक्ष में 309 सांसदों ने जबकि इसके विरोध में 305 सांसदों ने वोट किया।
2. इसके पक्ष में वोट करने वाले मंत्रियों ने कहा कि इस मामूली झटके से 2019 में ब्रिटेन के ईयू से निकलने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी।
3. जिन कंजरवेटिव सांसदों ने सरकार के विरुद्ध वोट किया है, उनमें से आठ पूर्व मंत्री हैं। इनमें से एक स्टीफन हैमंड हैं, जिन्हें वोट के बाद कंजरवेटिव पार्टी के उपाध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया गया।
4. सरकार का कहना है कि उसे मिले आश्वासनों के बावजूद ब्रेजिट विधेयक को लेकर मिली हार निराशाजनक है। ब्रेजिट को लेकर सरकार को पहली बार हार का सामना करना पड़ा है।
5. लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कोर्बिन ने कहा कि ईयू सम्मेलन की पूर्व संध्या पर टरीजा के लिए यह हार शर्मनाक है। इस सम्मेलन में ब्रेजिट पर चर्चा होनी है।

भारत और मोरक्को ने सहमति-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये

स्वास्थ्य सुविधा में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और मोरक्को ने सहमति-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। सहमति-ज्ञापन पर भारत की तरफ से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी.नड्डा और मोरक्को के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. अब्दुलकादिर अमारा ने हस्ताक्षर किये। इस अवसर पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आला अधिकारियों सहित मोरक्को का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल उपस्थित था।

दोनों देशों के बीच सहयोग के मुख्य क्षेत्र इस प्रकार हैं-

1. बाल हृदय रोग और कैंसर सहित गैर-संचारी रोग
2. औषधि नियमन एवं गुणवत्ता नियंत्रण
3. संचारी रोग
4. मातृत्व, बाल एवं पूर्व-प्रसव स्वास्थ्य
5. बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के आदान-प्रदान के लिए अस्पतालों के बीच सहयोग
6. स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पतालों के प्रबंधन और प्रशासन में प्रशिक्षण

एक दूसरा सहमति-ज्ञापन जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (जिपमर) और और मराकेश मोहम्मद विश्व विद्यालय अस्पताल के बीच हुआ। इस अवसर पर दोनों देशों के मंत्री मौजूद थे। दोनों देशों के संस्थानों ने टेली-मेडिसन के क्षेत्र में सहयोग पर सहमति व्यक्त की।

अर्थशास्त्र

ब्यूनस आयर्स घोषणा-पत्र

ब्यूनस आयर्स (अर्जेन्टीना) में चल रहे विश्व व्यापार संगठन के 11वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान व्यापार में महिलाओं की भागीदारी पर एक संयुक्त घोषणा-पत्र जारी किया गया, जिसे WTO के 119 सदस्य राष्ट्रों का अनुमोदन प्राप्त हुआ। इसे 'महिलाओं और व्यापार पर ब्यूनस आयर्स घोषणा-पत्र' नाम दिया गया। भारत ने इस घोषणा-पत्र का विरोध किया है।

क्या है

1. इस घोषणा पत्र में शामिल प्रावधानों के पालन से दुनिया में महिलाओं को बेहतर वेतन वाली नौकरियाँ मिलेंगी।
2. इससे संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भी सहायता मिलेगी।
3. साथ ही लैंगिक समानता पर आधारित सतत विकास लक्ष्य की ओर किये जा रहे प्रयासों को भी बल मिलेगा।
4. व्यापार गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी से 2025 तक वैश्विक GDP में 28 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि होने की संभावना है।

भारत क्यों विरोध किया है ?

1. भारत का कहना है कि यह घोषणा-पत्र एक लैंगिक मुद्दे को WTO से जोड़ता है, जबकि लैंगिक मुद्दे का व्यापार से कोई लेना-देना नहीं है।
2. यदि आज WTO में किसी लैंगिक मुद्दे को जगह दी जाती है, तो भविष्य में श्रम और पर्यावरणीय मानकों जैसे मुद्दे भी इस मंच पर जगह पाना चाहेंगे।
3. एक कोर व्यापारिक संगठन होने के नाते WTO को स्वयं को सिर्फ व्यापारिक मुद्दों तक सीमित रखना चाहिये।
4. उन्नत देश महिला-व्यापार संबंधी नीतियों में उच्च मानकों का उपयोग कर विकासशील देशों के निर्यात को प्रभावित कर सकते हैं और इससे विकासशील देशों में महिलाओं को मिलने वाले इंसेंटिव या प्रोत्साहन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
5. विभिन्न महिला संगठनों का रुख

6. विश्व के लगभग 160 से अधिक महिला संगठनों ने इस घोषणा पत्र पर आपत्ति जताई है। उनके अनुसार WTO के नियमों के महिलाओं पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों से निपटने की कोई व्यवस्था नहीं है।
7. यह घोषणा-पत्र लैंगिक भेद-भाव और शोषण को रोकने की WTO की नीतियों को ढकने का प्रयास है।
8. WTO की मुक्त व्यापार नीतियों का नुकसान सीमांत किसानों खासकर महिला किसानों को उठाना पड़ा है।

आरबीआई की मौद्रिक नीति

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी मौद्रिक नीति का ऐलान कर दिया। अपने ऐलान में आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। जिससे आपकी ईएमआई जस की तस रहेगी। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने मौद्रिक नीति का ऐलान करते हुए कहा कि ब्याज दर को 6 प्रतिशत से परिवर्तित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उर्जित पटेल ने तीसरी और चौथी तिमाही के लिये अनुमानित महंगाई दर 4.3 से बढ़ाकर 4.7 प्रतिशत कर दिया। जबकि आर्थिक वृद्धि के अनुमान को 6.7 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा।

क्या है

1. आरबीआई गवर्नर ने आगाह करते हुए कहा कि कृषि ऋण माफी, ईंधन पर उत्पाद शुल्क में आंशिक कमी, कई वस्तुओं पर जीएसटी दर घटाने से राजकोषीय लक्ष्य गड़बड़ा सकते हैं। इसके अलावा उर्जित पटेल ने इससे डिजिटल भुगतान को और प्रोत्साहित करने के लिए डेबिट कार्ड से लेनदेन पर शुल्कों को तर्कसंगत बनाने का फैसला किया।
2. रिजर्व बैंक गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा बैंकों को पूंजी उपलब्ध कराने के लिये पुनर्पूँजीकरण बॉर्ड पर सरकार के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैंकों को नई पूंजी उपलब्ध कराना उनमें केवल पूंजी डालना ही नहीं बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधारों को आगे बढ़ाना भी है।

RBI ने तीसरी बार चेताया बिटकॉइन में न करें निवेश

6 दिसम्बर के सत्र में क्रिप्टोकरंसी बिटकॉइन ने 12000 डॉलर का रिकॉर्ड हाई छुआ है। इस वर्चुअल करंसी में यह तेजी अमेरिकी डेरिवेटिव्स के नियामक की घोषणा के बाद देखने को मिली है। नियामक ने सीएमई ग्रुप इंक और सीबीओई ग्लोबल मार्केट को बिटकॉइन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट करने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि केंद्रीय बैंक ने लगातार तीसरी बार लोगों को इसमें निवेश करने के लिए आगाह किया है। 30 नवंबर को बिटकॉइन ने 10,000 डॉलर का स्तर पार कर लिया था लेकिन यह बढ़कर 12,135 डॉलर हो गया है। यही सब देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने देशभर के लोगों को बिटकॉइन में निवेश से आगाह करने के लिए फिर से चेतावनी जारी की है।

क्या है

1. 5 दिसंबर को RBI ने इस संबंध में पूर्व में जारी चेतावनी का उल्लेख किया है। साथ ही कहा है कि कई VC के मूल्यांकन में रैली और इनिशियल कॉइन पेशकशों (ICO) में तेज वृद्धि को देखते हुए हम अपनी चिंता को फिर दोहराते हैं।
2. बिटकॉइन का किसी मौद्रिक प्राधिकरण की ओर से नियमन नहीं होता है। इसमें ट्रेडिंग को मान्यता नहीं दी गई है। इसलिए वर्चुअल करंसी में ट्रेड करना काफी जोखिम भरा है।

क्या है बिटकॉइन:

1. बिटकॉइन एक वर्चुअल करंसी (क्रिप्टो करंसी) जैसी है जिसे एक ऑनलाइन एक्सचेंज के माध्यम से कोई भी खरीद सकता है। इसकी खरीद-फरोख्त से फायदा लेने के अलावा भुगतान के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है।
2. इसमें इस साल 900 फीसद से ज्यादा का उछाल दर्ज किया गया है। अगस्त 2011 में इसकी कीमत पहली बार 1000 डॉलर हुई थी इसके बाद 20 मई 2017 को यह 2000 डॉलर का हुआ था। उसके बाद से अब दिसंबर में इसकी कीमत 12000 डॉलर हो गई है।

RBI ने तय कीं नई MDR दरें

डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के इरादे से रिजर्व बैंक ने मर्चेट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) की नई दरें तय की हैं। खुदरा कारोबारियों को अब डेबिट कार्ड पेमेंट पर प्रति ट्रांजैक्शन 0.3 से 0.9 प्रतिशत एमडीआर देना होगा। एमडीआर की अधिकतम दर 1000 रुपये होगी। हालांकि छोटे कारोबारियों को एमडीआर कम देना होगा जबकि बड़े कारोबारियों के लिए इसकी दरें अधिक होंगी। एमडीआर की नई दरें एक जनवरी 2018 से प्रभावी होंगी।

क्या है

1. रिजर्व बैंक के मुताबिक सालाना 20 लाख रुपये टर्नओवर वाले कारोबारियों को पीओएस यानी प्वाइंट ऑफ सेल के जरिये डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर देना होगा और इसकी अधिकतम सीमा 200 रुपये होगी।
2. वहीं क्यूआर कोड के जरिये कार्ड से भुगतान स्वीकारने पर उन्हें 0.3 प्रतिशत एमडीआर देना होगा। इस मामले में भी अधिकतम चार्ज सिर्फ 200 रुपये होगा। हालांकि रिजर्व बैंक इस कदम को डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया कदम बता रहा है। लेकिन कारोबारी मान रहे हैं कि इससे नकद भुगतान को फिर से बढ़ावा मिल सकता है।
3. कोई व्यापारी डेबिट कार्ड से भुगतान स्वीकार करता है तो बैंक को उसे शुल्क देना होता है। आरबीआइ के अनुसार जिन व्यापारियों का सालाना कारोबार 20 लाख रुपये से अधिक है उन्हें पीओएस से हुए पेमेंट के प्रत्येक ट्रांजैक्शन के लिए 0.9 प्रतिशत एमडीआर देना होगा।
4. हालांकि इसकी अधिकतम सीमा 1000 रुपये होगी। इसी तरह अगर यह व्यापारी क्यूआर कोड के माध्यम से कार्ड से पेमेंट लेता है तो एमडीआर 0.80 प्रतिशत देना होगा और इसकी अधिकतम सीमा भी 1000 रुपये होगी।
5. नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने पिछले साल दिसंबर में 1000 रुपये तक के कार्ड से भुगतान पर एमडीआर चार्ज की अधिकतम सीमा 0.5 प्रतिशत तथा 1000 रुपये से 2000 रुपये के ट्रांजैक्शन पर एमडीआर चार्ज 0.5 प्रतिशत तय करने का फैसला किया था। इससे पहले 2000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन पर एमडीआर चार्ज 0.75 प्रतिशत तथा दो हजार रुपये से अधिक के ट्रांजैक्शन पर अधिकतम एक प्रतिशत एमडीआर चार्ज लगता था।

तीसरी सबसे आशावादी कंपनियां भारत की

नई भर्तियों के मामले में भारत तीसरा आशावादी देश है। यहां पर करीब 22 फीसद नियोक्ता अगले तीन महीनों के भीतर अन्य भर्तियों की उम्मीद कर रहे हैं, हालांकि इस पैमाने पर ताइवान हमसे आगे रहा है। यह जानकारी एक सर्वे के जरिए सामने आई है। प्रमुख स्टाफिंग कंसल्टेंसी मैनपावर ग्रुप इंडिया की ओर से आज जारी सर्वेक्षण के मुताबिक सभी सात क्षेत्रों में कार्यबल लाभ की उम्मीद थी और सभी चार क्षेत्रों में निगरानी की गई।

क्या है

1. सर्वे, जो कि पूरे देश में उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों में 4,500 से अधिक नियोक्ताओं के बीच आयोजित किया गया था कहा गया है कि नौकरी चाहने वालों के लिए अवसरों की उपलब्धता पिछली तिमाही के मुकाबले अधिक होने की उम्मीद है।
2. क्या है ताइवान की स्थिति: करीब 25 फीसद के रोजगार आउटलुक के साथ ताइवान इस लिस्ट में टॉप पर रहा है। यहां पर आगामी तीन महीनों के दौरान भर्तियों का रुख काफी आशावादी है, इसके बाद 24 फीसद के साथ जापान का नंबर आता है, इसके बाद 22 फीसद के साथ भारत तीसरे नंबर पर काबिज है।
3. इस सर्वे के लिए वैश्विक स्तर पर, मैनपावर ग्रुप ने 43 देशों और क्षेत्रों में लगभग 59,000 नियोक्ताओं का साक्षात्कार किया।

4. इस सर्वे में यह भी सामने आया है कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, नार्वे, पोलैंड, रोमानिया और यूनाइटेड स्टेट्स (अमेरिका) की कंपनियों के पास अगले पांच सालों के लिए एक मजबूत हायरिंग प्लान तैयार है।
5. इसके अलावा, हाल के दिनों में कुछ देशों में नौकरी बाजार में अस्थिरता देखी गई है, विशेष रूप से ब्राजील, चीन और भारत में।

आर्थिक असमानता लगातार बढ़ रही है

भारत में आय की असमानता ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर पर पहुंच गई है। एक अध्ययन के अनुसार 0.1 फीसद सबसे अमीर लोगों की संपदा, 50 फीसद सबसे गरीब आबादी की कुल संपत्ति से भी ज्यादा हो गई है। वर्ल्ड इनइक्वैलिटी लैब के अध्ययन में कहा गया है कि वर्ष 1980 से आर्थिक असमानता तेजी से बढ़ रही है।

क्या है

1. उसके अध्ययन में कहा गया है कि इस अवधि में असमानता 1947 में देश की आजादी के बाद के तीन दशकों के रुझान से विपरीत है। इन तीन दशकों में असमानता कम हुई थी। देश के 50 फीसद सबसे गरीब लोगों की आमदनी राष्ट्रीय औसत से कहीं तेज रफ्तार से बढ़ी थी।
2. यह रिपोर्ट अर्थशास्त्री फ्रैंकुडो एलवारेडो, लुकास चैनसेल, थॉमस पिकेटी, इमैनुअल सैज और गैब्रियल जुकमैन ने तैयार की है।
3. इसमें पिछले 40 वर्षों में ग्लोबलाइजेशन के असमान असर को दर्शाया गया है।
4. यह अध्ययन आय और संपदा में असमानता के सबसे विशाल आंकड़ों पर किया गया है। इसका उद्देश्य आर्थिक असमानता पर वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक बहस के जरिये इन तथ्यों से दुनिया को अवगत कराना है। इसके लिए नवीनतम और भरोसेमंद आंकड़ों को सार्वजनिक किया गया है।

पूँजी जुटाने के मामले में TCS टॉप पर

देश की शीर्ष 10 कंपनियों ने बाजार पूँजीकरण के मामले में बीते पांच वर्षों में 38.9 लाख करोड़ रुपये की पूँजी का सृजन किया है। टीसीएस ने इस सूची में लगातार पांचवी बार पहला स्थान हासिल किया है। यह जानकारी हाल ही की एक रिपोर्ट के जरिए सामने आई है। दिग्गज ब्रोकरेज कंपनी मोतीलाल ओसवाल की 22वीं एनुअल वेल्थ क्रिएशन स्टडी में पता चला है कि टीसीएस ने वर्ष 2012 से 2017 के दौरान कंपनी ने 2.50 लाख करोड़ रुपये की इन्वेस्टर्स वेल्थ सृजित की है।

क्या है

1. इस सूची में अगला नंबर निजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी का है जिसने 2.31 लाख करोड़ रुपये पूँजी का सृजन किया है।
2. वहीं, तीसरे नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.89 लाख करोड़ रुपये के साथ है। इससे पिछली स्टडी में रिलायंस इंडस्ट्रीज इस सूची में अपनी जगह नहीं बना पाई थी। इसके बाद आईटीसी 1.59 लाख करोड़ चौथे नंबर पर और मारुति सुजुकी पांचवें नंबर पर है।
3. मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज कंपनी का कहना है कि इन पांच वर्षों में 38.9 लाख करोड़ रुपये अबतक सबसे ज्यादा सृजित की गई राशि है।
4. अजंता फार्मा लगातार तीसरी बार सबसे तेजी से पूँजी सृजित करने वाली कंपनी है। वर्ष 2012 से वर्ष 2017 में कंपनी के स्टॉक प्राइज 29 गुना (96 फीसद सीएजीआर) बढ़ गए हैं। वहीं, मेटल/ माइनिंग, ट्रेडिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट टॉप पांच वेल्थ डिस्ट्रॉइंग सेक्टर रहे हैं।

छठे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हाट

छठे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हाट (आईटीएम) के आयोजन का शुभारंभ गुवाहाटी, असम में हो रहा है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, पूर्वोत्तर राज्य के सहयोग से 5 से 7 दिसंबर, 2017 तक इस हाट का आयोजन कर रहा है। असम के राज्यपाल श्री जगदीश मुखी, असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय पर्यटन सचिव श्रीमती रश्मि वर्मा और केंद्रीय मंत्रालयों तथा पूर्वोत्तर राज्यों के गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में इसका उद्घाटन करेंगे।

क्या है

1. छठे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हाट से भारत की “एक्ट ईस्ट पॉलिसी” पर ध्यान केंद्रित होने के साथ-साथ आसियान तथा दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं के गृह विशाल पूर्व एशिया क्षेत्र के साथ संबंध सुदृढ़ करने तथा भारत में उभरते हुए पर्यटन बाजार पर भी ध्यान केंद्रित होगा।
2. पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन को प्रोत्साहन देने पर विचार-विमर्श के साथ-साथ ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ के उद्देश्यों के तहत एशियान क्षेत्र के देशों के साथ लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने के साथ-साथ इन देशों के साथ पूर्वोत्तर राज्यों का संपर्क अधिक बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
3. इससे एशियान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच अंतर-क्षेत्रीय पर्यटन को विकसित करने में मदद मिलेगी। आईटीएम 2017 में पूर्वोत्तर राज्य विकास मंत्रालय द्वारा भी सक्रिय भागीदारी निभायी जाएगी, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन के विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान की जा सके।
4. छठे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हाट के आयोजन का उद्देश्य क्षेत्र में पर्यटन की संभावना को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के सामने प्रस्तुत करना है। समारोह से पूर्वोत्तर राज्यों के उद्यमियों और पर्यटन व्यापार से जुड़े व्यक्तियों को एक दूसरे से मिलने का अवसर मिलेगा।
5. कार्यक्रम से खरीददारों, मीडिया, सरकारी संस्थाओं और अन्य भागीदारों के बीच विचार-विमर्श संभव हो सकेगा। अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा तथा सिक्किम के राज्यों सहित भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर्यटन के आकर्षणों तथा उत्पादों से समृद्ध है। क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति, इसके पेड़-पौधे, पौराणिक परंपराओं तथा जीवन स्तर की समृद्ध धरोहर वाले प्रजातीय समुदाय, इसके त्यौहार, उत्सव, कला और शिल्प अवकाश के दौरान अपनी ओर बरबस आकर्षित करते हैं।
6. देश के विभिन्न भागों से तथा विश्व के चारों ओर से क्रेता तथा मीडिया प्रतिनिधि इस हाट में हिस्सा ले रहे हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विक्रेतओं से रूबरू हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में 29 देशों से 66 विदेशी प्रतिनिधि जिसमें भागीदार तथा मीडिया के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। इनमें मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, भूटान, ब्रुनेई, कनाडा, चीन, कंबोडिया, साइप्रस, फिजी, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, केन्या, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमा, नेपाल, नीदरलैंड, फिलीपींस, पुर्तगाल, सिंगापुर, स्पेन, तंजानिया, थाइलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, वियतनाम, तुर्की और दक्षिण कोरिया शामिल हैं, जिसमें पर्यटन उत्पाद आपूर्तिकर्ता इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीधे क्रेताओं तक पहुंचने में समर्थ होंगे।
7. अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन पूर्वोत्तर राज्यों में बारी-बारी से किया जाता है। इससे पूर्व मार्ट का आयोजन गुवाहाटी, तवांग, शिलांग, गंगटोक और इम्फाल में किया जा चुका है।

विज्ञान एवं तकनीकी

22वें एचडब्ल्यूपी सम्मेलन का उद्घाटन

माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने हाल ही में नई दिल्ली में एशियन हार्मोनाइजेशन वर्किंग पार्टी (एचडब्ल्यूपी) के 22वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। पांच दिवसीय सम्मेलन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) और राष्ट्रीय औषधि नियामक प्राधिकरण (एनडीआरए) द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एशिया और उसके

बाहर के क्षेत्रों में चिकित्सीय उपकरणों के नियमन के अभिसरण और एकरूपता के लिए दृष्टिकोण विकसित करने हेतु सुझाव देना तथा नियामकों एवं इस उद्योग के बीच ज्ञान तथा विशेषज्ञता के आदान-प्रदान में सुविधा प्रदान करना है।
क्या है

1. 30 सदस्य देशों तथा उद्योग के सदस्यों के राष्ट्रीय नियामकों की एशियन हार्मोनाइजेशन वर्किंग पार्टी (एचडब्ल्यूपी) का गठन 1999 में स्वैच्छिक लाभ निरपेक्ष संगठन के तौर पर किया गया था।
2. इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सीय उपकरण नियामक मंच (आईएमडीआरएफ) द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुरूप एशिया और अन्य क्षेत्रों में चिकित्सीय उपकरणों के नियमन पर नियामक एकरूपता को बढ़ावा देना है। एचडब्ल्यूपी आईएमडीआरएफ, डब्ल्यूएचओ, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) जैसे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर कार्य करता है।
3. सरकार का देश में चिकित्सीय उपकरण क्षेत्र में मेक इन इंडिया, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) तथा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी वैश्विक नियामक तरीकों के साथ बेहतर एकरूपता और पारदर्शी, पूर्वानुमान तथा सुदृढ़ विनियामक प्रणाली के लिए हाल ही में नियमन अर्थात् चिकित्सीय उपकरण नियम, 2017 लागू किया है।

हिमालयी क्षेत्र में तेज भूकंप के कारण का चला पता

स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने हिमालयी क्षेत्रों में आने वाले तेज भूकंप के कारण का पता लगा लिया है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत (लिथोस्फेयर) में मौजूद टेक्टॉनिक प्लेट की टक्कर से पहाड़ी क्षेत्रों में तेज भूकंप आता है। लिथोस्फेयर में सात बड़ी और कई छोटी टेक्टॉनिक प्लेट होती हैं। जितनी तेज गति से ये प्लेट आपस में टकराती हैं, तापमान उतना अधिक ठंडा हो जाता है। इसके कारण भूकंप की तीव्रता बढ़ जाती है। मालूम हो कि 2015 में नेपाल में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था। इसके एक साल बाद इटली के नार्सिया ने 6.2 तीव्रता के भूकंप का सामना किया। दोनों ही जगहों पर विनाशकारी भूकंप के कारण जान-माल को बहुत नुकसान हुआ था।

क्या है

1. इसके बाद से ही वैज्ञानिक भूकंप के भौतिक कारणों का पता लगाने की कोशिश में जुटे थे लेकिन कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया।
2. पहली बार शोधकर्ताओं ने 2डी मॉडल का निर्माण कर टेक्टॉनिक प्लेटों का अध्ययन किया।
3. अर्थ और प्लेनेटरी साइंस लेटर जर्नल में प्रकाशित इस शोध से जुड़े शोधकर्ताओं का कहना है कि ये प्लेट फिसलती और आपस में टकराती हैं जिससे पहाड़ों और ज्वालामुखियों में कंपन के कारण भूकंप आता है।

आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण

जमीन से हवा में मार करने में सक्षम स्वदेशी तकनीक से युक्त मिसाइल आकाश का आईटीआर रेंज चांदीपुर में कॉम्प्लेक्स 3 से सफल परीक्षण किया गया। मिसाइल का रडार, टेलीमेट्री और इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल प्रणाली के जरिए सभी स्तरों पर परीक्षण हुआ।

क्या है

1. इस मिसाइल को सेना में जमीन से हवा में कम दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइल के तौर पर शामिल किया गया है। यह पहली जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसमें रेडियो तरंगों के आधार पर अपने लक्ष्य को भेदने के लिए स्वदेशी तकनीक युक्त प्रणाली का प्रयोग किया गया है। इस सफल परीक्षण के बाद

भारत ने किसी भी तरह की जमीन से हवा में मार करने में सक्षम मिसाइल बनाने की क्षमता हासिल कर ली है।

8 ग्रहों वाला एक और सोलर सिस्टम

अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा को एक बड़ी सफलता मिली है। NASA के केपलर स्पेस टेलिस्कोप ने हमारे जितना बड़ा ही एक और सोलर सिस्टम ढूँढ निकाला है। दरअसल, यह स्टार सिस्टम पहले ही खोजा गया था, अब वहीं पर आठवें ग्रह की भी पहचान कर ली गई है। ऐसे में सूर्य या उस जैसे किसी स्टार की परिक्रमा करने के मामले में केपलर-90 सिस्टम की तुलना हमारे सौरमंडल से की जा सकती है।

क्या है

1. इस खोज में गूगल की ओर से आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (AI) की मदद ली गई, जो इंसानों के रहने योग्य ग्रहों की तलाश करने में काफी मदद करेगा।
2. केपलर-90 सोलर सिस्टम के इस आठवें ग्रह का नाम केपलर 90i है। गूगल और नासा के इस प्रॉजेक्ट द्वारा हमारे जैसे ही सौर मंडल की खोज से इस बात की उम्मीद बड़ी है कि ब्रह्मांड में किसी ग्रह पर ऐलियन मौजूद हो सकते हैं।
3. केपलर-90 के ग्रहों की व्यवस्था हमारे सौर मंडल जैसी ही है। इसमें भी छोटे ग्रह अपने स्टार से नजदीक हैं और बड़े ग्रह उससे काफी दूर मौजूद हैं।
4. NASA के अनुसार, इस खोज से पहली बार स्पष्ट होता है कि दूर कहीं स्टार सिस्टम में हमारे जैसे ही परिवार मौजूद हो सकते हैं। यह सौर मंडल हमसे करीब 2,545 प्रकाश वर्ष दूर है।

अपने सौरमंडल से है काफी समानता

1. टेक्सस यूनिवर्सिटी के नासा सगन पोस्टडॉक्टरल फेलो एवं खगोल विज्ञानी एंड्रयू वांडबर्ग ने कहा, 'नया ग्रह पृथ्वी से करीब 30 फीसदी बड़ा माना जा रहा है। हालांकि यह ऐसी जगह नहीं है, जहां आप जाना चाहेंगे।'
2. उन्होंने बताया कि यहां काफी चट्टानें हैं और वातावरण भी घना नहीं है। सतह का तापमान काफी ज्यादा है और इससे लोग झुलस सकते हैं। वांडबर्ग के मुताबिक सतह का औसत तापमान करीब 800 डिग्री फारनहाइट हो सकता है।

DNA से तैयार हुई मोना लीजा

लॉस एंजलिस में वैज्ञानिकों ने इतालवी कलाकार लियोनार्दो दा विंची की मशहूर कलाकृति मोना लीजा की सबसे छोटी प्रति डीएनए की मदद से तैयार की है। अमेरिका के कैलिफोर्निया इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलजी के अनुसंधानकर्ताओं ने एक ऐसा सस्ता तरीका खोजा है जिसके जरिए डीएनए एकत्र होकर खुद को एक क्रम में सजा लेते हैं।

क्या है

1. यह क्रम इस तरह से व्यवस्थित होता है कि इसके पैटर्न को पूरी तरह अपनी रुचि के अनुसार ढाला जा सकता है।
2. इससे ऐसा कैनवस तैयार होता है जो किसी भी किस्म की छवि को प्रदर्शित कर सकता है।
3. डीएनए को मूलतः जीवित चीजों की अनुवांशिक सूचनाएं पता लगाने में इस्तेमाल किया जाता है लेकिन यह रसायनों का एक ढांचा बनाने में भी समर्थ है।

विश्व की सबसे भारी मछली

विश्व का सबसे भारी 'बेनी फिश' जापान में मिली है। बताया जा रहा है कि विश्व की सबसे भारी 'बेनी फिश' यानी ओस्टीइक्थीज जापान में मिली है, जिसका वजन 2300 किलोग्राम है। बोनी फिश या हड्डीदार मछलियां ऐसी मछलियों की श्रेणी में आती हैं जिनके अंदरूनी ढांचे कार्टिलेज के बदले हड्डी के बने होते हैं।

क्या है

1. हिरोशिमा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अनुसार शुरू में माना जा रहा था कि यह मछली सामान्य मोला मोला सनफिश प्रजाति की है लेकिन यह मोला अलेक्सड्रिनी सनफिश प्रजाति की है। जिसके बाद इसे विश्व की सबसे भारी हड्डीदार मछली होने का खिताब मिला।
2. 'इक्थीआलजिकल' रिसर्च पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार एक हजार से ज्यादा दस्तावेज और नमूनों की जांच की गई। कुछ दस्तावेज तो 500 साल पुराने भी थे।
3. गिनीज बुक ऑफ रिकार्ड्स में पहले मोला मोला प्रजाति की मछली को विश्व की सबसे भारी मछली का खिताब हासिल है लेकिन इस शोध के बाद पता चला है कि ये मोला मोला नहीं मोला एल्क्सजेंड्रिनी है।

सौर हवाओं से पूरी तरह सुरक्षित है मंगल का वायुमंडल

मंगल ग्रह का वायुमंडल सौर हवाओं के प्रभावों से पूरी तरह सुरक्षित है। धरती की तरह दो चुंबकीय ध्रुवों की गैरमौजूदगी के बावजूद इसपर सौर हवाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक नए अध्ययन में यह बात सामने आई है। वर्तमान में मंगल ग्रह एक ठंडा और शुष्क ग्रह है जिसकी सतह पर धरती के वायुमंडलीय दबाव से एक प्रतिशत कम दबाव है। हालांकि ग्रह की कई भूगर्भीय विशेषताएं यह दिखाती हैं कि यहां करीब तीन से चार साल पहले एक हाइड्रोलॉजिकल चक्र सक्रिय था। उस वक्त एक सक्रिय हाइड्रोलॉजिकल चक्र को ज्यादा गर्म जलवायु और घने वायुमंडल की जरूरत रही होगी जो एक बेहद गहरा ग्रीनहाउस प्रभाव पैदा कर सकने में सक्षम हो।

क्या है

1. एक आम कल्पना में माना जाता है कि सौर हवाओं ने मंगल के वायुमंडल को धीरे-धीरे खत्म कर दिया और ग्रीनहाउस प्रभाव को बढ़ा दिया होगा जिससे अंततः हाइड्रोलॉजिकल चक्र नष्ट हो गया हो।
2. स्वीडन की उमिया यूनिवर्सिटी के रॉबिन रैमस्टेड ने बताया कि मंगल पर धरती की तरह चुंबकीय ध्रुव नहीं होते, लेकिन सौर हवाएं ऊपरी वायुमंडल में तरंगे बनाती हैं जिससे कि यहां एक तरह का चुंबकीय क्षेत्र :इंड्यूस्ड मैग्नेटोस्फियर : बन जाता है।
3. लंबे अर्से तक यह माना जाता रहा है कि स्वतः पैदा नहीं होने वाला यह चुंबकीय क्षेत्र मंगल के वायुमंडल को सुरक्षित रखने में पर्याप्त नहीं है। 'हालांकि हमारे प्रमाण कुछ और दर्शाते हैं।' पूर्व की अवधारणाओं के उलट यह दर्शाते हैं कि यह चुंबकीय क्षेत्र भी मंगल के वायुमंडल को सौर हवाओं के प्रभाव से सुरक्षित रखता है।

सूपरमून के बाद अब होगी तारों की बारिश

अनंत रहस्यों को स्वयं में छिपाए आकाश हमेशा से हमारे और वैज्ञानिकों के लिए जिज्ञासा का केंद्र रहा है। कभी इंद्रधनुष तो कभी सूर्य और चंद्र ग्रहण से हमारी आंखें अपनी ओर खींचे ही रखता है। अभी कुछ दिन पहले ही हम सूपरमून जैसी भौगोलिक घटना से रूबरू हुए। अब एक और मौका आ रहा है जब पूरी दुनिया की निगाहें आकाश की ओर होंगी। दरअसल, जल्द ही हम अंतरिक्ष में तारों की बारिश होते हुए देखेंगे। आसमान में होने वाली इस घटना को जेमिनिड्स कहा जाता है।

क्या है

1. जेमिनिड्स में कई तारे और उल्का झुंड में धरती पर बरसते हुए दिखाई देते हैं। यह खूबसूरत नजारा 13 और 14 दिसंबर की रात को दुनिया के लगभग हर इलाके में देखा जा सकेगा।
2. वैज्ञानिकों के मुताबिक, यह उल्कापात या मीटियोर की ये बारिश सालना प्रक्रिया है। यह हर वर्ष दिसंबर में होती है। इस बार 13 और 14 तारीख को ये अपनी चरम पर होगी। इसे विश्व के उत्तरी हिस्सों के सभी देशों में नग्न आंखों से देखा जा सकेगा।

3. दरअसल हर साल जब पृथ्वी 3200 फ़ैथोन नाम की पथरीली अंतरिक्ष वस्तु के पास से गुजरती है तो इसके आस-पास का कचरा पृथ्वी के वातावरण में आने के कारण जल जाता है।
4. जब अंतरिक्ष के कचरे के ऐसे कई छोटे-छोटे तत्व एक साथ जलते हैं तो ये धरती पर आसमान से हो रही किसी चमकीली तारों की बारिश जैसे लगते हैं। इसे आप नासा की वेबसाइट पर जाकर लाइव देख सकते हैं।

समुद्र में छिपे सांस्कृतिक अवशेष

कृत्रिम उपग्रहों और रिमोट सेंसिंग तकनीक वाली भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग प्राकृतिक व सांस्कृतिक संसाधनों को समझने के लिए बड़े पैमाने पर हो रहा है। अब भारतीय वैज्ञानिकों ने इस प्रौद्योगिकी का उपयोग तमिलनाडु के तट पर समुद्र में डूबे खंडहरों को खोजने के लिए किया है। गोवा स्थित राष्ट्रीय समुद्र-विज्ञान संस्थान (एनआइओ) के वैज्ञानिकों ने भू-स्थानिक तकनीक की मदद से महाबलीपुरम, पूमपुहार, त्रेंकबार और कोरकाई के समुद्र तटों और उन पर सदियों पूर्व बसे ऐतिहासिक स्थलों का विस्तृत अध्ययन किया है। इससे पता चला है कि महाबलीपुरम और उसके आसपास तटीय क्षरण की दर 55 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि पिछले 1500 वर्षों से इसी दर से महाबलीपुरम की तटरेखा में क्षरण हुआ होगा, तो निश्चित रूप से उस समय यह तटरेखा लगभग 800 मीटर समुद्र की तरफ रही होगी। इसी आधार पर पुष्टि होती है कि समुद्र के अंदर पाए गए ये खंडहर भूभाग पर मौजूद रहे होंगे। स्थानिक बदलावों के कारण समुद्र-तटीय धरोहरें क्षतिग्रस्त हुई

क्या है

1. अध्ययन दल के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. सुंदरेश के मुताबिक, समय के साथ तमिलनाडु की समुद्र तट-रेखा में आए स्थानिक बदलावों के कारण समुद्र-तटीय धरोहरें क्षतिग्रस्त हुई हैं।
2. भू-स्थानिक तकनीक पर आधारित शोध परिणाम भविष्य में समुद्री ऐतिहासिक व सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण में सतर्कता बरतने के लिए कारगर साबित हो सकते हैं।
3. वैज्ञानिकों के अनुसार तटीय क्षरण और समुद्र के स्तर में परिवर्तन के कारण तमिलनाडु के लगभग 900 किलोमीटर लंबे समुद्र तट पर स्थित महाबलीपुरम, अरीकमेडू, कावेरीपट्टनम, त्रेंकबार, नागापट्टनम, अलगांकुलम, कोरकाई और पेरियापट्टनम जैसे कई बंदरगाह पिछली सदियों में नष्ट हो गए या फिर समुद्र में डूब गए।
4. 1954 से 2017 तक तमिलनाडु की तटरेखा में आए बदलावों का पता लगाने के लिए प्रमाणित टोपोग्राफिक शीट और उपग्रह से प्राप्त प्रतिबिंब का उपयोग किया गया। रिमोट सेंसिंग से प्राप्त चित्रों के विश्लेषण से पाया गया कि पिछले 41 वर्षों में महाबलीपुरम में 177 मीटर और पूमपुहार के तटों में 36 वर्षों के दौरान 129 मीटर क्षरण हुआ है।
5. अध्ययन के दौरान गोताखोरों ने समुद्र के अंदर विभिन्न मंदिरों को पाया है, जो उपग्रह द्वारा प्राप्त जानकारीयों की पुष्टि करते हैं। वर्तमान कावेरी मंदिर से 25 मीटर की दूरी पर एक मीटर की गहराई में समुद्र के समानांतर मिली ईटनुमा संरचनाएं मिली हैं।

विविध

विश्वकप 2023 की मेजबानी करेगा भारत

विश्वकप 2019 इंग्लैंड और वेल्स में खेला जायेगा। इसके बाद विश्वकप 2023 (50 ओवर) का आयोजन भारत में किया जायेगा। इसके अलावा चैम्पियन्स ट्रॉफी 2021 का आयोजन भी भारत में ही होगा। इससे पहले साल 1987, 1996 और 2011 में भारत 50 ओवरों के विश्वकप का सफल आयोजन कर चुका है। 2011 विश्वकप का सफल आयोजन भारत में हुआ था। इसे रिकॉर्ड दर्शकों ने भी देखा था। 2011 में भारत में खेले गए विश्वकप का विजेता भी भारत ही रहा था।

क्या है

1. विश्वकप 2011 भारत ने महेन्द्र सिंह धोनी की कप्तानी में खेला था। इसका फाइनल मैच भारत और श्रीलंका के बीच मुंबई में खेला गया था।
2. इस मैच को भारत ने 6 विकेट से जीत लिया था। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 274 रन बनाए थे। इसके जवाब में उतरी टीम इंडिया ने 4 विकेट खोकर 48.2 ओवर में ही मैच जीत लिया था।
3. यह मैच भारतीय क्रिकेट इतिहास के लिए पन्नों में दर्ज हो गया। विश्वकप जीतने के साथ ही क्रिकेट के भगवान ने इसी मैच के बाद संन्यास से लिया था। सचिन विश्व के इकलौते खिलाड़ी हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल मैचों में 100 शतक लगाए हैं।

भारतीयों को UN में मिला 'पावर ऑफ वन' अवॉर्ड

संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पहले दीपावली पावर ऑफ वन पुरस्कार से एक भारतीय महिला समेत छह शीर्ष राजनयिकों को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार और अधिक आदर्श, शांतिपूर्ण और सुरक्षित दुनिया बनाने में उनके योगदान को देखते हुए दिया गया।

क्या है

1. अमेरिका की डाक सेवा ने पिछले वर्ष दीपावली के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किया था। ये पुरस्कार इसी की पहली वर्षगांठ पर दिए गए।
2. पुरस्कार पाने वालों में संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन के निवर्तमान राजदूत मैथ्यू रेक्राफ्ट, संयुक्त राष्ट्र में लेबनान के राजदूत नवाफ सलाम और यूएन विमिन की भारतीय प्रमुख लक्ष्मी पुरी शामिल हैं।
3. एक वक्तव्य में कहा गया कि इस समारोह का आयोजन बेलारूस, जॉर्जिया और भारत के स्थायी मिशनो ने संयुक्त रूप से किया।
4. अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, श्री लंका, थाइलैंड, स्पेन, कुवैत और अल्जीरिया समेत करीब दो दर्जन देश इसके सह आयोजक थे।
5. आयोजन यहां न्यू यॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में ट्रस्टीशिप काउंसिल चौबर्स में हुआ।

रामसेतु पर विदेशी भूगर्भविज्ञानियों की भी मुहर

संकीर्ण राजनीतिक कारणों से अपने देश के लोग भले ही रामसेतु की ऐतिहासिकता और प्रामाणिकता को खारिज करते रहते हैं और उसे काल्पनिक बताते हैं, लेकिन भूगर्भ वैज्ञानिकों, आर्किओलाजिस्ट की टीम ने सैटेलाइट से प्राप्त चित्रों और सेतु स्थल के पत्थरों और बालू का अध्ययन करने के बाद यह पाया है कि भारत और श्रीलंका के बीच एक सेतु का निर्माण किए जाने के संकेत मिलते हैं। वैज्ञानिक इसको एक सुपर ह्यूमन एचीवमेंट मान रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार भारत-श्रीलंका के बीच 30 मील के क्षेत्र में बालू की चट्टानें पूरी तरह से प्राकृतिक हैं, लेकिन उन पर रखे गए पत्थर कहीं और से लाए गए प्रतीत होते हैं। यह करीब सात हजार वर्ष पुरानी हैं जबकि इन पर मौजूद पत्थर करीब चार-पांच हजार वर्ष पुराने हैं।

क्या है

1. भारत के दक्षिणपूर्व में रामेश्वरम और श्रीलंका के पूर्वोत्तर में मन्नार द्वीप के बीच उथली चट्टानों की एक चैन है। इस इलाके में समुद्र बेहद उथला है।
2. समुद्र में इन चट्टानों की गहराई सिर्फ 3 फुट से लेकर 30 फुट के बीच है। इसे भारत में रामसेतु व दुनिया में एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इस पुल की लंबाई लगभग 48 कि.मी. है।
3. रामसेतु भौतिक रूप में उत्तर में बंगाल की खाड़ी को दक्षिण में शांत और स्वच्छ पानी वाली मन्नार की खाड़ी से अलग करता है, जो धार्मिक एवं मानसिक रूप से दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ता है।

4. रामसेतु पुल भारत के दक्षिण-पूर्वी तट के किनारे तमिलनाडु स्थित रामेश्वरम द्वीप और श्रीलंका के उत्तर-पश्चिमी तट मन्नार द्वीप के बीच स्थित है।

5. जियोलॉजिस्ट डॉक्टर एलेन लेस्टर बताते हैं कि हिंदू मान्यता के मुताबिक इस पुल को भगवान राम ने बनवाया था। साइंस चैनल ने व्हाट 'ऑन अर्थ एनसिएंट लैंड एंड ब्रिज' नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। जिसमें भू-वैज्ञानिकों की तरफ से यह विश्लेषण इस ढांचे के बारे में किया गया है। वैज्ञानिकों के विश्लेषण के बाद पत्थर के बारे में रहस्य और गहरा गया है कि आखिर ये पत्थर यहां पर कैसे पहुंचा और कौन लेकर आया है।

भू-वैज्ञानिकों ने क्या निष्कर्ष निकाला है

1. भू-वैज्ञानिकों ने नासा की तरफ से ली गई तस्वीर को प्राकृतिक बताया है।
2. वैज्ञानिकों ने अपने विश्लेषण में यह पाया कि 30 मील लंबी यह श्रृंखला चैन मानव निर्मित है।
3. अपने विश्लेषण में भू-वैज्ञानिकों को यह पता चला कि जिस सैंड पर यह पत्थर रखा हुआ है ये कहीं दूर जगह से यहां पर लाया गया है।
4. उनके मुताबिक, यहां पर लाया गए पत्थर करीब 7 हजार साल पुराना है।
5. जबकि, जिस सैंड के ऊपर यह पत्थर रखा गया है वह मजह सिर्फ चार हजार साल पुराना है।
6. हालांकि, कुछ जानकार इसे पांच हजार साल पुराना मानते हैं जिस दौरान रामायण में इसे बनाने की बातें कही गई हैं।

रामसेतु से जुड़े कुछ अनकहे तथ्य

1. रामसेतु पुल को श्रीराम के निर्देशन में कोरल चट्टानों और रीफ से बनाया गया था। जिसका विस्तार से उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है।
2. रामसेतु की उम्र रामायण के अनुसार 3500 साल पुराना बताया जाता है, तो कुछ इसे आज से 7000 हजार वर्ष पुराना बताते हैं। कुछ का मानना है कि यह 17 लाख वर्ष पुराना है।
3. रामसेतु का उल्लेख कालीदास की रघुवंशम में सेतु का वर्णन है। इसके अलावा स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण और ब्रह्म पुराण में भी श्रीराम के सेतु का उल्लेख मिलता है।
4. भारतीय सेटेलाइट और अमेरिका के अन्तरिक्ष अनुसंधान संस्थान 'नासा (NASA)' ने उपग्रह से खींचे गए चित्रों में भारत के दक्षिण में धनुषकोटि तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में पम्बन के मध्य समुद्र में 48 किमी चौड़ी पट्टी के रूप में उभरे एक भू-भाग की रेखा दिखती है, उसे ही आज रामसेतु या राम का पुल माना जाता है।
5. प्राचीन वास्तुकारों ने इस संरचना की परत का उपयोग बड़े पैमाने पर पत्थरों और गोल आकार की विशाल चट्टानों को कम करने में किया और साथ ही साथ कम से कम घनत्व तथा छोटे पत्थरों और चट्टानों का उपयोग किया, जिससे आसानी से एक लंबा रास्ता तो बना ही, साथ ही समय के साथ यह इतना मजबूत भी बन गया कि मनुष्यों व समुद्र के दबाव को भी सह सके।

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाएगा

माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 14 दिसंबर, 2017 को नई दिल्ली में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। इस अवसर पर केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री राज कुमार सिंह भी उपस्थित रहेंगे।

क्या है

1. विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के महत्व के बारे में जन जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाता है।
2. जागरूकता फैलाने के रूप में बीईई ऊर्जा उपभोग को कम करने में उद्योगों के प्रयासों को मान्यता प्रदान करने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान करता है। बीईई ऊर्जा संरक्षण विषय पर वार्षिक चित्रकला प्रतियोगिता के राष्ट्रीय विजेताओं को भी पुरस्कृत करता है।
3. इस वर्ष राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता में 1.22 करोड़ से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया था और 322 औद्योगिक ईकाइयों तथा प्रमुख क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2017 के लिए प्रतिभागिता की थी।
4. माननीय राष्ट्रपति इस वर्ष के राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार और राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता पुरस्कार प्रदान करेंगे। श्री कोविंद पुरस्कार विजेताओं के चित्रों की प्रदर्शनी भी देखेंगे। कार्यक्रम के दौरान उद्योग क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता की उपलब्धियों पर लघु फिल्म भी दिखाई जाएगी।

संसद हमले की 16वीं बरसी

संसद पर हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर शहीद जवानों को याद किया और उनके साहस को नमन किया, जिन्होंने 13 दिसंबर, 2001 को भारत के लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी संसद हमले में शहीद हुए जवानों को याद किया। 13 दिसंबर, 2001 को हमारे बहादुर सैनिकों ने संसद भवन पर हुए आतंकी हमले को नाकामयाब कर अनुकरणीय साहस दिखाया। हम सुरक्षाबलों की वीरता और राष्ट्रीय सेवा को सलाम करते हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

क्या है

1. संसद पर हुए आतंकी हमले को 16 साल हो चुके हैं, लेकिन उसका जखम आजतक देश भुला नहीं सका है। आतंकियों ने भारत के लोकतंत्र के मंदिर को चोट पहुंचाने की कोशिश की, हमारे वीर जवानों ने उनके नापाक इरादों को अपना जीवन कुर्बान करके ध्वस्त कर दिया।
2. 13 दिसंबर, 2001 को संसद पर हुए आतंकी हमले में संसद भवन के गार्ड, दिल्ली पुलिस के जवान समेत कुल 9 जवान शहीद हुए थे। 16 साल पहले आज ही के दिन संसद पर आतंकी हमला हुआ था।
3. सफेद एंबेसडर कार में आए सभी पांच आतंकी सेना की वर्दी में संसद भवन में दाखिल हुए थे। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के इन आतंकियों ने संसद भवन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं।
4. संसद हमले में शामिल चार आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली की पोटा अदालत ने 16 दिसंबर, 2002 को चारों आतंकी मोहम्मद अफजल, शौकत हुसैन, अफसान और सैयद रहमान गिलानी को दोषी करार दिया था।
5. सुप्रीम कोर्ट ने सैयद अब्दुल रहमान गिलानी और नवजोत संधू को बरी कर दिया था, लेकिन मोहम्मद अफजल की मौत की सजा को बरकरार रखा था और शौकत हुसैन की मौत की सजा को घटाकर 10 साल कर दिया था। इसके बाद 9 फरवरी, 2013 को अफजल गुरु को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सुबह 8 बजे फांसी पर लटका दिया गया था।

मोबाइल इंटरनेट स्पीड में बहुत पीछे है भारत

मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में दुनिया में भारत का स्थान 109वां है तथा फिक्स्ड ब्रॉडबैंड के मामले में 76वां है, जबकि इसमें 15 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऊकला (Ookla) के नवंबर के स्पीडटेस्ट वैश्विक सूचकांक से यह जानकारी मिली है। एक बयान में कहा गया कि 2017 की शुरुआत में, भारत में औसत मोबाइल डाउनलोड स्पीड 7.65 एमबीपीएस था, लेकिन साल के अंत तक यह बढ़कर 8.80 फीसदी हो गया, जोकि 15 फीसदी की बढ़ोतरी है।

क्या है

- हालांकि मोबाइल की स्पीड में मामूली वृद्धि हुई है, लेकिन फिक्स्ड ब्रॉडबैंड की स्पीड में नाटकीय वृद्धि हुई है। जनवरी में फिक्स्ड ब्रॉडबैंड की औसत स्पीड 12.12 एमबीपीएस थी, जबकि नवंबर में बढ़कर यह 18.82 एमबीपीएस हो गई, जो कि करीब 50 फीसदी की छलांग है।
- नवंबर में दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल स्पीड नॉर्वे में दर्ज की गई, जो 62.66 एमबीपीएस रही। फिक्स्ड ब्रॉडबैंड में सिंगापुर सबसे आगे रहा, जहां 153.85 एमबीपीएस की औसत डाउनलोड स्पीड दर्ज की गई।
- ऊकला के सह-संस्थापक और महाप्रबंधक डोग सटेल्लस ने कहा, भारत में मोबाइल और फिक्स्ड ब्रॉडबैंड दोनों की स्पीड में तेजी से सुधार हो रहा है। यह सभी भारतीय ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है, चाहे वे किसी भी ऑपरेटर का कोई भी प्लान क्यों न लें। हालांकि भारत को स्पीड के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों तक पहुंचने में काफी समय लगेगा।

इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत से आगे हैं ये देश-

1. नेपाल - 99वां स्थान
2. नाइजीरिया - 102वां स्थान
3. सूडान - 103वां स्थान
4. इंडोनेशिया - 106वां स्थान
5. श्रीलंका - 107वां स्थान

सबसे तेज मोबाइल इंटरनेट वाले 5 देश-

1. नार्वे - पहला स्थान
2. नीदरलैंड दूसरा - स्थान
3. आइसलैंड तीसरा - स्थान
4. सिंगापुर चौथा - स्थान
5. माल्टा पांचवां - स्थान

नहीं रहे 'डीएनए फिंगर प्रिंट' के जनक

काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति पद्मश्री डा. लालजी का 10 दिसम्बर को निधन हो गया। वह 70 साल के थे। लालजी सिंह को डीएनए फिंगर प्रिंट का जनक भी कहा जाता है। उनकी जिन्म नाम से कलवारी में ही एक संस्था है। इसमें रिसर्च का कार्य होता है। डा. लालजी सिंह वर्तमान में सीसीएमबी, हैदराबाद के निदेशक भी थे। बताया जाता है कि दिल्ली के तंदूर हत्याकांड को सुलझाने में उनका बहुत योगदान था।

क्या है

- लालजी सिंह का जन्म 5 जुलाई 1947 को हुआ था। यूपी के जौनपुर जिले के सदर तहसील और सिकरारा थानाक्षेत्र के कलवारी गांव के निवासी थे। इनके पिता का नाम स्व. ठाकुर सूर्य नारायण सिंह था। इंटरमीडिएट तक शिक्षा जिले में लेने के बाद उच्च शिक्षा के लिए 1962 में बीएचयू गए, जहां उन्होंने बीएससी, एमएससी और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की।
- 1971 में देश में पहली बार 62 पन्नों का उनकी पीएचडी की थीसिस जर्मनी के फॉरेन जनरल में छपा था। उसके बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी के रिसर्च यूनिट (जूलॉजी) जेनेटिक में फेलोशिप के तहत 1971-1974 तक रिसर्च करने का मौका मिला।
- 1974 में पहली बार कॉमनवेल्थ फेलोशिप के तहत UK जाने का मौका मिला। काफी दिन वहां रिसर्च के बाद भारत लौट आए।
- 1987 में कोशकीय और आण्विक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद (सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी) में साइंटिस्ट के तौर पर नियुक्त हुए। 1999 से 2009 तक यही डायरेक्टर के पद पर तैनात रहे।

चक्रवात 'ओखी'

चक्रवात ओखी के कारण तमिलनाडु और केरल के दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश हुई जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। इस चक्रवात के कन्याकुमारी से 60 किलोमीटर दक्षिण में रहने के समय अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अंदेशा जताया गया था।

क्या है

1. भारतीय मौसम विज्ञान की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार 65-75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चल रही है और दक्षिणी केरल में अगले 48 घंटों और दक्षिणी तमिलनाडु में 24 घंटों के भीतर इसके 85 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है।
2. कन्याकुमारी के अलावा तिरुवनैलवेली और तूतीकोरिन जिले भी बारिश के कारण परेशानी का सामना कर रहे हैं। दक्षिणी तमिलनाडु में कई जिलों में शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है।
3. केरल की सरकार ने भी आधिकारिक मशीनरी को हाई अलर्ट पर रखा है और तट से 100 मीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को दूसरे स्थान पर जाने का आदेश दिया है।
4. राज्य सरकार ने नौसेना, तटरक्षक और वायु सेना से मदद भी मांगी है।

वर्ल्ड एड्स डे

दुनिया भर में हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से साल 1988 से इसकी शुरुआत की गई थी। दुनिया भर में फिलहाल 3.67 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं जबकि भारत 21 लाख रोगियों के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा HIV पीड़ित लोगों की सूची में तीसरे नंबर पर आता है। साल 2015 में इस बीमारी की वजह से दुनिया में 11 लाख जबकि भारत में 68 हजार मौतें हुई हैं। दुनिया भर में एड्स और HIV पीड़ित लोगों के प्रति भेदभाव की घटनाएं भी लगातार सामने आती रहीं हैं।

भारत में क्या है स्थिति

1. यूएनएड्स के मुताबिक भारत में सिर्फ 36 % लोगों को ही एड्स का उपचार मिल पाता है। बाकी 64 % लोगों को इसका उपचार मिल ही नहीं पाता है।
2. हालांकि इसी रिपोर्ट के अनुसार 2005 से 2013 के बीच एड्स से हुई मौतों की संख्या में करीब 38 % की गिरावट आई है। इसकी वजह उपचार के साधनों का विस्तार माना जाता है।
3. एड्स के ज्यादातर मामले पूर्वोत्तर के राज्यों और दक्षिण के राज्यों में हैं। इस बीच बिहार और मध्य प्रदेश में भी एड्स पीड़ितों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। यौन कर्मियों में भी एड्स के मामले बढ़ते जा रहे हैं। यौन कर्मियों की संख्या करीब 868000 बताई जाती है जिसमें से लगभग 18 % एड्स से पीड़ित हैं।

क्या हैं वजहें

1. भारत में एड्स की प्रमुख वजह है प्रवासी श्रमिक और दूसरे देशों में जानेवाले नौकरीपेशा लोग, असुरक्षित यौन संबंध और असुरक्षित रक्तदान।
2. हालांकि भारतीय सेना इसे आधिकारिक तौर पर नहीं स्वीकारती है लेकिन कुछ गैरसरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संस्थाओं के अनुसार सेना में भी एड्स के मामले बढ़ते जा रहे हैं।
3. खास तौर पर ऐसे सैनिक जो दूरदराज के इलाकों में तैनात हैं उनमें और उनसे एड्स के फैलने की आशंका रहती है। अगर नैको के आंकड़े देखें तो एड्स के प्राथमिक उपचार से लेकर सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट तक एक मरीज के उपचार में करीब 6500 से लेकर 28500 का खर्च आता है। लिहाजा एड्स का इलाज काफी मंहगा है। हालांकि हाल के वर्षों में भारत में स्थानीय स्तर पर जेनेरिक दवाओं के उत्पादन से भी एड्स की रोकथाम में व्यापक सफलता मिली है।

क्या है HIV और AIDS

1. एचआईवी सबसे पहली बार 19वीं सदी की शुरुआत में जानवरों में मिला था। माना जाता है की इंसानों में यह चिंपांजी से आया।
2. 1959 में कांगो के एक बीमार आदमी के खून का नमूना लिया गया। कई साल बाद डॉक्टरों को उसमें एचआईवी वायरस मिला। माना जाता है कि यह पहला एचआईवी संक्रमित व्यक्ति था।

3. 1981 में एड्स की पहचान हुई। लॉस एंजिलिस के डॉक्टर माइकल गॉटलीब ने पांच मरीजों में एक अलग किस्म का निमोनिया पाया। इन सभी मरीजों में रोग से लड़ने वाला तंत्र अचानक कमजोर पड़ गया था।
4. ये पांचों मरीज समलैंगिक थे इसलिए शुरुआत में डॉक्टरों को लगा कि यह बीमारी केवल समलैंगिकों में ही होती है। इसीलिए एड्स को ग्रिड यानी गे रिलेटिड इम्यून डेफिशिएंसी का नाम दिया।
5. बाद में जब दूसरे लोगों में भी यह वायरस मिला तो पता चला कि यह धारणा गलत है। 1982 में ग्रिड का नाम बदल कर एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम रखा गया।
6. 1983 में सेन फ्रांसिस्को में समलैंगिकों ने इस विषय पर जागरूकता फैलाने के लिए प्रदर्शन भी किए।
7. 1983 में फ्रांस के लुक मॉन्टेगनियर और फ्रांसोआ सिनूसी ने एलएवी वायरस की खोज की। इसके एक साल बाद अमेरिका के रॉबर्ट गैलो ने एचटीएलवी 3 वायरस की पहचान की। 1985 में पता चला कि ये दोनों एक ही वायरस हैं।
8. 1985 में मॉन्टेगनियर और सिनूसी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जबकि गैलो ने अपने परीक्षण का पेटेंट कराया। 1986 में पहली बार इस वायरस को एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस का नाम मिला।

एड्स की दवा

1. 1987 में पहली बार एड्स से लड़ने के लिए दवा तैयार की गई। लेकिन इसके कई साइड इफेक्ट्स थे और मरीजों को दिन में कई खुराक लेनी पड़ती थी।
2. 90 के दशक के अंत तक इसमें सुधार आया। कुछ क्विक टेस्ट भी आए। जैसे तस्वीर में ओरा क्विक। इसका दावा था कि लार के परीक्षण से 20 मिनट में बताया जा सकता है कि शरीर में वायरस है या नहीं।
3. 1991 में पहली बार लाल रिबन को एड्स का निशान बनाया गया। यह एड्स पीड़ित लोगों के खिलाफ दशकों से चले आ रहे भेदभाव को खत्म करने की एक कोशिश थी।
4. संयुक्त राष्ट्र ने मलेरिया और टीबी की तरह एड्स को भी महामारी का नाम दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक 2012 के अंत तक एक करोड़ लोगों को एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी मिल रही है।
5. लेकिन बाकी एक करोड़ 60 लाख लोग इससे 2013 में भी वंचित हैं। अधिकतर लोग यह बात नहीं समझ पाते कि अगर वक्त रहते वायरस का इलाज शुरू कर दिया जाए तो एड्स से बचा जा सकता है।

भोपाल गैस कांड का आज भी खतरा बना हुआ है

दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक हादसों में शूमार भोपाल गैस कांड के 33 साल बाद भी यूनियन कार्बाइड कारखाने में 346 टन जहरीला कचरा मौजूद है। इस जहरीले कॅमिकल को नष्ट करने का निर्णय ही नहीं हो पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इंदौर के पास पीथमपुर में 10 टन कचरे का निष्पादन प्रयोग के बतौर किया गया, लेकिन इस कवायद का पर्यावरण पर कितना दुष्प्रभाव हुआ, इसकी रिपोर्ट का खुलासा होना बाकी है। बचे हुए जहरीले कचरे को कैसे ठिकाने लगाया जाए, इसे लेकर सरकार आज भी धर्मसंकट में है। पर्यावरण से जुड़े इस बेहद संवेदनशील मामले पर सरकार का कहना है कि उसके पास जहरीले कचरे को निपटाने की सुविधाएं और विशेषज्ञ नहीं हैं। यह जहरीला कचरा यूनियन कार्बाइड कारखाने के 'कवर्ड शैड' में रखा गया है। कचरे का आधिपत्य प्रदेश के गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग के पास है। त्रासदी के करीब साढ़े तीन दशक बाद भी पर्यावरण पर खतरे की तलवार लटकी हुई है। मध्य प्रदेश सरकार इस मुद्दे पर केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का मुंह ताक रही है।

केंद्र के पास लंबित है रिपोर्ट

1. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 13-18 अगस्त 2015 तक पीथमपुर में 'रामके' कंपनी के इंसीनरेटर में जहरीला कचरा जलाया गया।

2. ट्रीटमेंट स्टोरेज डिस्पोजल फेसिलिटीज (टीएसडीएफ) संयंत्र से इसके निष्पादन में पर्यावरण पर कितना असर पड़ा, इसकी रिपोर्ट केंद्रीय वन-पर्यावरण मंत्रालय को चली गई है।
3. **मामले में 3 मार्च 2016 के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी नहीं हुई। असर क्या हुआ, इसकी जानकारी नहीं मिली है।**
4. इस जहरीले कचरे को भोपाल से पीथमपुर तक ले जाना भी बड़ा चुनौतीपूर्ण है। खास पैकिंग में विशेष लीक प्रूफ एवं सील प्रूफ बड़े वाहनों में इसकी ढुलाई की जानी है।
5. **जीपीएस युक्त विशेष रंग एवं संकेतकों वाले इन वाहनों के ड्राइवरों को इस काम का प्रशिक्षण दिया जाता है। इन गाड़ियों पर बड़े-बड़े अक्षरों में खतरनाक (हैजार्ड) लिखा रहता है। आपातकालीन स्थिति में किसे सूचना देना है, उसका नंबर भी मौजूद रहता है।**

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी

1. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस पूरे मामले की निगरानी कर रहा है। बोर्ड का कहना है कि उसने भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग अधिष्ठाता मेसर्स यूनियन कार्बाइड लि. भोपाल को 17 मार्च 2020 तक प्राधिकार/सम्मति जारी की है।
2. **रामके ग्रुप के मेसर्स एमपी वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पीथमपुर (कामन ट्रीटमेंट स्टोरेज व डिस्पोजल फेसिलिटी) को 19 जुलाई 2019 तक प्राधिकार एवं 31 अक्टूबर 2018 तक सम्मति जारी की है।**

नहीं रहे अभिनेता शशि कपूर

शशि कपूर का 79 साल की उम्र में निधन हो गया। मुंबई के कोकिला बेन अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। वह काफी समय से बीमार थे।

क्या है

1. हिन्दी फिल्म और थियेटर जगत के शुरुआती स्टार पृथ्वीराज कपूर के घर 18 मार्च, 1938 को जन्मे शशि कपूर ने चार वर्ष की आयु से अपने पिता द्वारा निर्मित और निर्देशित नाटकों में काम करना शुरू कर दिया था।
2. शशि कपूर को तीन बार नेशनल अवॉर्ड मिल चुका है। 1979 में शशि द्वारा निर्मित फिल्म जुनून को बेस्ट फीचर फिल्म अवॉर्ड मिला। 1994 में फिल्म 'मुहाफिज' के लिए उन्हें स्पेशल ज्युरी अवॉर्ड।
3. शशि कपूर को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। उनके बचपन का नाम बनबीर राज कपूर था। शशि स्कूल में नाटकों में हिस्सा लेना चाहते थे। उनकी यह इच्छा वहां तो कभी पूरी नहीं हुई, लेकिन उन्हें यह मौका अपने पिता के 'पृथ्वी थियेटर्स' में मिला।

ट्विटर पर मोदी बरकरार

सोशल मीडिया का खास तवज्जो देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर पर जलवा बरकरार है। ट्विटर इंडिया की 2017 की रिपोर्ट (इयर ऑन ट्विटर) में वह सर्वाधिक फॉलो किए जाने भारतीयों की सूची में पहले पायदान पर हैं। इससे बड़ी बात यह है उनके फॉलोअर की संख्या 52 फीसदी की ग्रोथ इस साल हुई है। फॉलोअर की ग्रोथ में वह तीसरे नंबर पर हैं। इस साल क्रिकेटर विराट कोहली के फॉलोअर की संख्या में सर्वाधिक ग्रोथ हुई। उनके फॉलोअर ग्रोथ 61 फीसदी रही, जबकि सचिन तेंदुलकर के फॉलोअर 56 फीसद बढ़े। ट्विटर इंडिया की ताजा लिस्ट में प्रधानमंत्री अकेले राजनेता है जो न सिर्फ टॉप टेन में हैं बल्कि शीर्ष पर हैं। बाकी सात स्थानों पर बॉलीवुड के सितारों का कब्जा है। इस सूची में जगह पाने वाले विराट कोहली अकेले वर्तमान खिलाड़ी हैं। ट्विटर इंडिया की सालाना रिपोर्ट के शीर्ष 10 लोकप्रिय अकाउंट में पहली बार क्रिकेटर विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर को जगह मिली है। तो वहीं इस सूची में स्थान पाने वाली दीपिका पादुकोण अकेली महिला हैं। वह सूची में सातवें नंबर पर हैं। उनके फॉलोअर में 34 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा महिला विश्व कप पर खूब बात हुई। महिला खेलों में वर्ल्ड कप का हैशटैग शीर्ष पर रहा।

जीएसटी पर जोरदार चर्चा:

1. नोटबंदी के सरकार के दूसरे बड़े कदम जीएसटी की ट्विटर पर खूब चर्चा हुई। समाचार और राजनीति के वर्ग में यह हैशटैग दीवाली हैशटैग के दूसरे नंबर पर रहा।
2. तो वहीं तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेडियो बातचीत का कार्यक्रम मन की बात तीसरे नंबर पर रहा। ट्विटर इंडिया के अनुसार मन की बात कार्यक्रम पर ट्विटर पर यूजर के बीच अच्छी बातचीत हुई। मनोरंजन के वर्ग में बाहुबली-2 का हैशटैग शीर्ष पर रहा।
3. दूसरा नंबर बिगबॉस के सीजन 11 के हैशटैग के नाम रहा। खेल में भारत बनाम पाकिस्तान मैच के हैशटैग ने रिकॉर्ड बनाया। यह मैच सर्वाधिक ट्वीट पाने वाला एक दिवसीय मैच बना। कुल 1.6 मिलियन ट्वीट हुए। मनोरंजन में बाहुबली-2, तमिल फिल्म मेरसल, बिग बॉस-11 और साल के अंत में हुए पद्मावती विवाद में सुर्खियों में रहे।

ये मुद्दे रहे सुर्खियों में:

1. नोटबंदी का एक साल
2. भारतीय राष्ट्रपति चुनाव
3. जस्टिस फॉर जलीकट्टू
4. ट्रिपक तलाक
5. राम रहीम की गिरफ्तारी

पॉलिटिको पावर लिस्ट में शामिल हुई भारतीय

पॉलिटिको ने 2018 की पहली पावर लिस्ट में भारतीय मूल की अमेरिकी महिला सांसद प्रमिला जयपाल को शामिल किया है। उन्हें यह स्थान सदन में विरोध का नेतृत्व करने के लिए दिया गया है। पावर लिस्ट में शामिल 18 लोगों में 52 वर्षीय जयपाल को पांचवां स्थान मिला है। वह भारतीय मूल की पहली अमेरिका महिला हैं जिनका नाम पॉलिटिको के पावर लिस्ट में शामिल किया है। पत्रिका के मुताबिक, 2018 में पूरे देश भर के 18 राजनेताओं, कार्यकर्ताओं और कार्यकारियों को शामिल किया गया है जो 2018 में बड़ी भूमिका के लिए तैयार हैं। पत्रिका के अनुसार, जयपाल तेजी से बढ़ती हुई लोकतांत्रिक स्टार और राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की मुखर आलोचक हैं। उन्होंने सदन में विरोधी के नेता के रूप में काम किया है।

क्या है

1. उनके दोस्त और रिपब्लिकन सभा के नए साथी सदस्य रो खन्ना के हवाले से पॉलिटिको ने बताया है कि कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस के पहले उपाध्यक्ष से लेकर उन्होंने कैपिटल हिल पर नागरिक अधिकारों और प्रवासी सुधार के लिए अथक अधिवक्ता के रूप में काम किया है।
2. पॉलिटिको में बताया गया है कि जयपाल भारतीय प्रतिनिधि सभा में काम करने वाली पहली भारतीय-अमेरिकी महिला हैं जो शायद ही कभी कोई चुनौती लेने से पीछे रहती हों।

दिव्यांग सेवा पुरस्कार

शारीरिक रूप से अशक्त लोगों के अधिकारों को लेकर जागरूकता फैलाने और उनकी जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक भारतीय डॉक्टर एवं दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ता को अमेरिका में प्रतिष्ठित हेनरी विस्कार्डी अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। 40 साल के डॉ सत्येंद्र सिंह नई दिल्ली स्थित यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में फिजियोलॉजी (शरीर विज्ञान) के असोसिएट प्रफेसर हैं।

क्या है

1. वह यह सम्मान हासिल करने वाले पहले भारतीय हैं। यह अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार पहली बार मार्च, 2013 में दिया गया था।
2. विस्कार्डी सेंटर ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी दिव्यांग अधिकार नेता और विस्कार्डी सेंटर एवं न्यूयार्क के हेनरी विस्कार्डी सेंटर के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी जॉन डी कॅप ने पुरस्कार दिए।

3. 2014 के भारतीय लोकसभा चुनाव को शारीरिक रूप से अशक्त लोगों के लिए सुगम्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सिंह ने कहा, “मैं यह पुरस्कार दुनिया भर में भेदभाव से लड़ रहे शारीरिक रूप से अशक्त हर व्यक्ति के दृढ़ संकल्प को समर्पित करता हूँ।”
4. उन्होंने कहा, “मुझे यहां अमेरिका में यह पुरस्कार हासिल करते समय अपने सीने पर भारतीय झंडे का बैज लगाते हुए बेहद गर्व महसूस हुआ। ”

ग्लोबल थिंक्स लिस्ट में टॉप पर रही भारतीय

भारतीय मूल की कैलिफोर्निया की सीनेटर कमला हैरिस प्रतिष्ठित ‘फॉरन पॉलिसी पत्रिका की 2017 की’ ग्लोबल थिंक्स सूची में शीर्ष पर काबिज हैं। सूची में अमेरिकी राजदूत निक्की हेली के साथ भारतीय अमेरिकी स्टैंड-अप कॉमेडियन हसन मिनहाज ने भी जगह बनाई। इस सूची में उन लोगों को जगह दी जाती है, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अप्रत्याशित तरीकों से अपनी छाप छोड़ी है।

क्या है

1. ‘ग्लोबल थिंक्स की वार्षिक सूची जारी करते हुए’ फॉरन पॉलिसी ने कहा “इसमें ऐसे लोग हैं जो 2017 को परिभाषित करते हैं।” इस साल 100 की बजाय 50 लोगों की ही सूची जारी की गई है।
2. पत्रिका ने कहा कि कमला हैरिस के इस सूची में शीर्ष पद काबिज होने से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में डेमोक्रेटिक पार्टी को एक उम्मीद मिलती है।
3. कमला की मां भारतीय और पिता जमैका निवासी है। कमला अमेरिकी सीनेट चुनी गई पहली भारतीय-अमेरिकी हैं। कमला एकमात्र अश्वेत सीनेट भी हैं, उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के दावेदार के तौर पर भी देखा जाता है।

बच्चों की आईक्यू कम करता है प्रदूषण

प्रदूषण से सिर्फ दिल्ली ही नहीं दुनिया भर के ज्यादातर विकसित और विकासशील देश भी जंग लड़ रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के छह दिवसीय दौरे में आए लंदन के मेयर सादिक खान ने राजधानी के महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल में बच्चों से मुलाकात के दौरान दिल्ली में प्रदूषण के लिए चिंता जाहिर की। उन्होंने प्रदूषण के खिलाफ जंग में सी-40 ग्रुप के एक साथ मिलकर लड़ने की योजना पर भी बात की। इस क्लाइमेट लीडरशिप ग्रुप में सी-40 में चालीस शहर प्रदूषण के खिलाफ एक साथ हैं। इनमें बेंगलुरु व दिल्ली का नाम भी शामिल है।

क्या है

1. सादिक खान ने बताया कि लंदन अब प्रदूषण के खिलाफ नई हाइटेक एअर क्वालिटी सेंसर तकनीक का ट्रायल करने जा रहा है। इस के जरिए शहर के सौ से लेकर 1000 स्थानों पर वायु प्रदूषण पर नजर रखी जा सकती है। लंदन इस तकनीक के परिणाम भारत से भी साझा करेगा।
2. आस-पास जलते हुए कचरे या निर्माण कार्य के चलते उड़ती धूल की शिकायत व्हाट्स एप पर की जा सकती है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने इस तरह की शिकायत के लिए दो व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं। पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने अलग-अलग विभागों के साथ बैठक करके प्रदूषण पर रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी ली।
3. वायु प्रदूषण न सिर्फ आपके फेफड़े खराब करता है, बल्कि नौनिहालों के दिमाग पर भी बुरा असर डालता है। वायु प्रदूषण आईक्यू को कम करने के साथ स्मृति लोप लाता है।
4. यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह बच्चों में चिंता, विकास संबंधी बीमारियों को भी जन्म देता है। दुनिया भर में 1.70 करोड़ बच्चे विश्व में वायु प्रदूषण से प्रभावित हैं।

- इनमें से 1.20 करोड़ बच्चे दक्षिण एशियाई देशों में हैं। ये बच्चे प्रदूषण के अंतरराष्ट्रीय मानकों छह गुना ज्यादा प्रदूषित वातावरण में रहने को मजबूर हैं। नवंबर में दिल्ली और उत्तर भारत में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, तब हवा मानकों से 10 से 12 गुना तक ज्यादा जहरीली हो गई।

‘साइलंस ब्रेकर्स’ बना टाइम का ‘पर्सन ऑफ द इयर’

यौन उत्पीड़न के खिलाफ शुरू किए गए साइलंस ब्रेकर्स अभियान को टाइम मैगजीन ने ‘पर्सन ऑफ द इयर’ घोषित किया है। उल्लेखनीय है कि हॉलिवुड के निर्माता-निर्देशक हार्वी वाइंस्टाइन और अन्य पुरुषों से जुड़ा यौन शोषण का मामला सामने आने के बाद इस कैम्पेन की शुरुआत हुई थी। अमेरिकन ऐक्ट्रेस ऐलिसा मिलानो ने इसके खिलाफ #MeToo का इस्तेमाल किया था, जो देखते ही देखते दुनियाभर में पॉप्युलर हो गया।

क्या है

- महिलाएं और यहां तक कि पुरुषों ने भी #MeToo और दूसरे हैशटैग के साथ यौन उत्पीड़न के खिलाफ अपनी चुप्पी तोड़ी और अपना दर्द साझा किया।
- इस कैम्पेन में बॉलिवुड हस्तियों ने भी हिस्सा लिया और यौन उत्पीड़न से जुड़ी अपनी कहानी शेयर की। एनबीसी के ‘टुडे’ शो में इसकी घोषणा की गई जहां लंबे समय से होस्ट रहे मैट को प्रताड़ना के आरोपों के बाद हाल ही में निकाला गया है।
- ‘पर्सन ऑफ द इयर’ की फाइनलिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग भी रहे हैं।

सशस्त्र सेना झंडा दिवस

सशस्त्र सेना ध्वज दिवस के अवसर पर पीएम मोदी केंद्रीय सैनिक बोर्ड के अधिकारियों से मुलाकात की। इस मौके पर पीएम मोदी के कपड़े पर सैनिकों की ओर से सशस्त्र सेना ध्वज लगाया गया। भारतीय सेना के लिए 7 दिसंबर एक अहम दिन है। इस दिन को पूरा देश आर्म्ड फोर्सेज डे यानी सशस्त्र सेना झंडा दिवस के जरिए उन्हें याद करता है। इसकी शुरुआत 1949 में हुई थी और इसका मकसद सेनाओं को उनका सही सम्मान देना था।

क्या है

- वर्ष 1947 को मिली आजादी के बाद सरकार के सामने सैनिकों के रख-रखाव के लिए जरूरी पैसे की कमी सामने आई। नागरिकों में सैनिकों के परिवारों के देखभाल की जिम्मेदारी की भावना को पैदा करना इस दिवस के गठन का अहम मकसद था।
- 28 अगस्त 1949 को रक्षा मंत्री के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने हर वर्ष सात दिसंबर को झंडा दिवस मनाने का सुझाव दिया। इसके जरिए लोगों को छोटे-छोटे झंडे दिए जाते हैं और बदले में डोनेशन लिया जाता है।
- सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष की 1993 में स्थापना की गई। आम लोग 10 रुपए से लेकर 10 लाख रुपये तक सैनिकों और उनके परिवार के कल्याण के लिए दे सकते हैं।
- देश में केंद्रीय सैनिक बोर्ड के तहत इस फंड को एकत्र किया जाता है और इसकी देखरेख होती है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड भी रक्षा मंत्रालय का ही हिस्सा है।

भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार

भारत की प्रथम महिला फोटो पत्रकार होमई वयरवाला का आज (9 दिसंबर) 104वां जन्मदिन है। इस मौके पर गूगल ने डूडल बनाकर उन्हें याद किया। उन्होंने 15 अगस्त 1947 में लाल किले पर ध्वजारोहण समारोह की तस्वीरें खींची थीं। होमई का जन्म नौ दिसंबर 1913 को एक पारसी परिवार में हुआ था।

क्या है

1. मुंबई में पली-बढ़ीं होमी ने फोटोग्राफी की शिक्षा जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से ली। होमी व्यारवाला की तस्वीरें आजाद भारत से पूर्व और उसके बाद की कहानी कहती हैं। उनकी पहली तस्वीर बॉम्बे क्रॉनिकल में प्रकाशित हुई थी।
2. सन 1942 में दिल्ली आ गई थी, जहां उन्होंने ब्रिटिश सूचना सेवा की कर्मचारी के तौर पर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी घटनाओं की तस्वीर खींची थी। वह 1930 से 1970 के बीच एक मात्र प्रोफेशनल फोटो पत्रकार थी।
3. उन्होंने लार्ड माउंटबेटन की विदाई, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के दाह संस्कार की तस्वीरें भी खींची थी।
4. उन्होंने संक्रमण काल में देश की सामाजिक और राजनीतिक जीवन को कैमरे में कैद किया। उन्हें जनवरी 2011 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।

45 फीसदी लोगों ने दी रिश्तत: सर्वे

एक सर्वे में पाया गया है कि भारत में 45 फीसदी लोगों ने पिछले साल रिश्तत दी है। 'ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल' द्वारा यह सर्वे 11 राज्यों में कराया गया। पिछले साल कराए गए सर्वे में 43 फीसदी लोगों द्वारा रिश्तत दिए जाने की बात सामने आई थी। 34,696 लोगों में से 37 फीसदी का मानना है कि एक साल में भ्रष्टाचार बढ़ गया है वहीं 14 फीसदी लोगों का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले करप्शन घटा है।

क्या है

1. पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में 71 फीसदी लोगों का कहना था कि यहां भ्रष्टाचार बढ़ा है। महाराष्ट्र में केवल 18 प्रतिशत लोगों ने ही कहा कि उनके राज्य में करप्शन बढ़ा है।
2. दिल्ली में लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। 33% लोगों का कहना था कि भ्रष्टाचार बढ़ा है वहीं 38 फीसदी लोगों ने कहा कि स्थिति जस की तस है। यहां 28 फीसदी लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार कम हुआ है। यूपी इस मामले में दूसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश के 21 फीसदी लोगों ने करप्शन कम होने की बात कही।
3. 'ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल' ने बताया कि निचले स्तर पर ही ज्यादातर भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं। उन्होंने कहा, 'एक राष्ट्रीय सर्वे के मुताबिक 84 फीसदी रिश्तत का लेनदेन नगरपालिका, पुलिस, टैक्स, बिजली, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से जुड़े विभागों में होता है।'
4. संस्था के मुताबिक 9% रिश्तत केंद्र सरकार के विभागों को दी गई जैसे, पीएफ, आयकर विभाग, सेवाकर विभाग, रेलवे आदि। 51 फीसदी लोगों का कहना है कि सरकार ने भ्रष्टाचार को घटाने की दिशा में कदम नहीं उठाए हैं। देश में 9 राज्य ऐसे हैं जिनमें लोकायुक्त नहीं हैं।

गुलरुख गुप्ता को SC से राहत

गुजरात की पारसी महिला गुलरुख गुप्ता के अपने समाज से बाहर हिंदू पुरुष से शादी करने पर पारसी 'मंदिर' में प्रवेश से रोक लगा दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उसे राहत दी है। गुलरुख ने अहमदाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती याचिका दायर की थी। कोर्ट के अनुसार अब वह पारसी मंदिरों में प्रवेश कर सकती है।

क्या है

1. पारसी महिला के हिन्दू पुरुष से शादी करने का मामला गुजरात की बालसाड पारसी ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह महिला को पिता के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए टावर आफ साइलेंस में जाने की इजाजत देने को तैयार है।

2. इससे पहले उसे बाहर शादी करने के कारण मना कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने भी महिला को पारसी रीति-रिवाज में हिस्सा लेने की मनाही के पारसी ट्रस्ट के फैसले को सही ठहराया था और कहा था कि विवाह के बाद महिला का धर्म पति के धर्म में तब्दील हो गया है।
3. इसके बाद महिला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अपना हक मांगा था। महिला का कहना था कि उसने हिन्दू पुरुष से स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी की थी, धर्म परिवर्तन नहीं किया था। उसे पारसी रिवाज से पिता के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने का हक मिलना चाहिए।
4. सुप्रीम कोर्ट ने महिला की याचिका पर गुजरात की बालसाड पारसी ट्रस्ट से महिला की मांग पर विचार कर जवाब देने को कहा था। जिसके लिए ट्रस्ट ने आज कोर्ट में सहमति जताई।

वर्ड ऑफ द इयर

ऑक्सफर्ड डिक्शनरीज ने 'Youthquake' को 2017 का वर्ड ऑफ द इयर घोषित किया है। इसका मतलब मिलेनियल वोटर्स के बीच 'राजनीतिक जागृति' होता है। मीडिया रिपोर्टों में यह जानकारी दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल 1960 के दशक में Vogue पत्रिका के संपादक ने किया था। उस समय डायना रीलैंड ने इसका इस्तेमाल फैशन, म्यूजिक और व्यवहार में अचानक आए बदलाव के लिए किया था।

क्या है

1. ऑक्सफर्ड इंग्लिश डिक्शनरी यूथक्वेक को '1960 के दशक में स्टूडेंट्स और युवाओं के बीच कट्टर राजनीतिक और सांस्कृतिक उथल-पुथल की श्रृंखला' के तौर पर परिभाषित करती है।
2. डिक्शनरीज ने कहा कि हाल में इसके इस्तेमाल को फिर से देखा गया। इस शब्द के द्वारा उन युवाओं के बारे में कहा गया जो राजनीतिक बदलाव चाहते हैं।
3. ऑक्सफर्ड डिक्शनरीज के कैसपर ग्रैथॉल ने कहा कि यह एक आसान विकल्प नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा कि 2017 के दौरान रोजाना भाषणों में यूथक्वेक का इस्तेमाल 5 गुना तक बढ़ गया।
4. ब्रिटेन में यूथक्वेक का इस्तेमाल जून में हुए आम चुनावों में बढ़-चढ़कर हुआ। ऑक्सफर्ड डिक्शनरीज ने कहा है कि वर्ड ऑफ द इयर एक शब्द या अभिव्यक्ति है जिसने सालभर लोगों का ध्यान खींचा और इसे अखबारों, किताबों, ब्लॉग्स आदि में बराबर प्रयोग किया गया। पिछले साल 'post-truth' को वर्ड ऑफ द इयर चुना गया था।

हीमोफीलिया का इलाज हुआ संभव

वैज्ञानिकों ने हीमोफीलिया के उपचार के लिए नई दवा विकसित करने में सफलता पाई है। यह जीन थेरेपी दवा इस विकार से रोगियों को निजात दिलाने में प्रभावी पाई गई है। इस विकार के चलते सामान्य रूप से रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है। मामूली चोट में भी बहुत ज्यादा खून बह जाता है। आंतरिक रक्तस्राव का भी खतरा रहता है। नतीजतन जान जोखिम में पड़ सकती है।

क्या है

1. शोधकर्ताओं के अनुसार, हीमोफीलिया ए पीड़ितों पर एक साल तक जीन थेरेपी दवा की एकल उपचार विधि आजमाई गई।
2. यह दवा रक्त का थक्का बनने में मददगार प्रोटीन का स्तर सामान्य करने और रोगियों को ठीक करने में प्रभावी पाई गई।
3. ब्रिटेन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन पासी ने कहा, 'हमारे पास अब यकीनन ऐसी क्षमता है जिसमें एकल उपचार के उपयोग से हीमोफीलिया पीड़ितों में बदलाव लाया जा सकता है। यह बड़ी उपलब्धि है।'